सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 21, नई दिल्ली । बुधवार, 03 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए जीवन में सफलता मिले या ना मिले परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही।

03 सुनीता केजरीवाल के मोर्चा संभालते ही,बीजेपी ने बदली रणनीति, बांसुरी स्वराज को लाए सामने
06 उत्तर-दक्षिण विभाजन की झूठी कहानी
08 बीजेडी नही मिले उम्मीदवार; कांग्रेस से नेताओं को लाकर पार्टी दिखा रही ताकत!

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहा है सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा, जिंदगी बचाने को हाईवे पर बनाएं ट्रामा सेंटर

दिल्ली-NCR में सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर प्रशासन हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे ट्रामा सेंटर बनवाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काफी घायल इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं।

एनसीआर में कहीं भी हाईवे पर नहीं दी गई है अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर की सुविधा, हाईवे का निर्माण करने के साथ ही ट्रामा सेंटर बनाने पर भी जोर देना चाहिए, हाईवे- एक्सप्रेस-वे पर हर 15 से 20 किलोमीटर पर होना चाहिए ट्रामा सेंटर

संजय बाटला

नईदिल्ली/गुरुग्राम। जिंदगी अनमोल है। शासन-प्रशासन को यह पता है। यह भी पता है कि हादसे में एक की मौत नहीं होती है बल्कि एक मौत से पूरा परिवार तबाह हो जाता है। साल दर साल मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हादसे के शिकार लोगों को समय पर इलाज न मिलना है। हादसा होने के आधे से पौन घंटे के भीतर इलाज शुरू हो जाना चाहिए लेकिन ट्रामा सेंटरों की सुविधा न होने से इलाज शुरू होने में समय लग जाता है। नतीजा यह होता है कि काफी घायल इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं।

कब तक सड़कों पर खत्म होती रहेंगी जिंदगियां?

जिंदगी बचानी है तो हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे जगह-जगह अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर की सुविधा विकसित करनी होगी अन्यथा सड़कों पर जिंदगियां खत्म होती रहेंगी। कहा जाता है कि समय व ईंधन बचाने के लिए हाईवे व एक्सप्रेस-वे पर जोर देना आवश्यक है। जब जिंदगी ही नहीं बचेगी फिर हाईवे व एक्सप्रेस-वे बनाकर क्या करेंगे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे को दुनिया का बेहतर एक्सप्रेस-वे बताया जा रहा है। इस एक्सप्रेस-वे के किनारे भी अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर की सुविधा नहीं है। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिंदगी बचाने को लेकर शासन-प्रशासन कितना गंभीर है।

हादसों में मौत के आंकड़ा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हर साल औसतन 1200 लोगों की मौत होती है। आइटी, आइटी इनेबल्ड, टेलीकाम, आटोमोबाइल एवं गारमेंट सेक्टर में पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाले गुरुग्राम में हर साल औसतन 400 लोगों की मौत होती है। प्रस्तुत है गुरुग्राम से यह रिपोर्ट-

हाईवे व एक्सप्रेस-वे किनारे आवश्यक है ट्रामा सेंटर

हाईवे व एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार काफी अधिक होती है। अधिकतर हाईवे पर अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक वाहनों की रफ्तार निर्धारित है। अधिकतर वाहनों की लगभग इतनी रफ्तार होती ही है। कुछ वाहनों की रफ्तार 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है।

खासकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, यमुना एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-पानीपत हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस-वे पर अधिकतर वाहनों की रफ्तार औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऐसे में हादसे होने की आशंका रहती है। जब तक चालक संभलते हैं तब तक हादसा हो जाता है।

वाहनों की रफ्तार अधिक होने की वजह से हादसा होने पर काफी गंभीर चोट लगती है। खासकर सिर में चोट लगने पर तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। यदि ट्रामा सेंटर नजदीक में हो तो तत्काल इलाज शुरू हो सकता है। इससे अधिकतर लोगों की जिंदगी बच सकती है।

कनेक्टिविटी बेहतर करने के साथ-साथ समय व ईंधन बचाने के लिए हाईवे व एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। मेरा सवाल है कि किसके लिए कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। कनेक्टिविटी बेहतर करने की चिंता करने से पहले जिंदगी बचाने की चिंता करनी चाहिए। जब तक जिंदगी बचाने की चिंता नहीं की जाएगी तब तक हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ट्रामा सेंटर विकसित करने पर जोर नहीं दिया जाएगा। मानता हूं कि कुछ लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, इस वजह से हादसे होते हैं। अधिकतर लोग दूसरों की गलती से हादसों के शिकार होते हैं। इंसानियत यही है कि सभी को समय पर इलाज मिलना चाहिए। इलाज तभी मिलेगा जब ट्रामा सेंटर की सुविधा होगी।

-- डॉ. एनके जैन, पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा

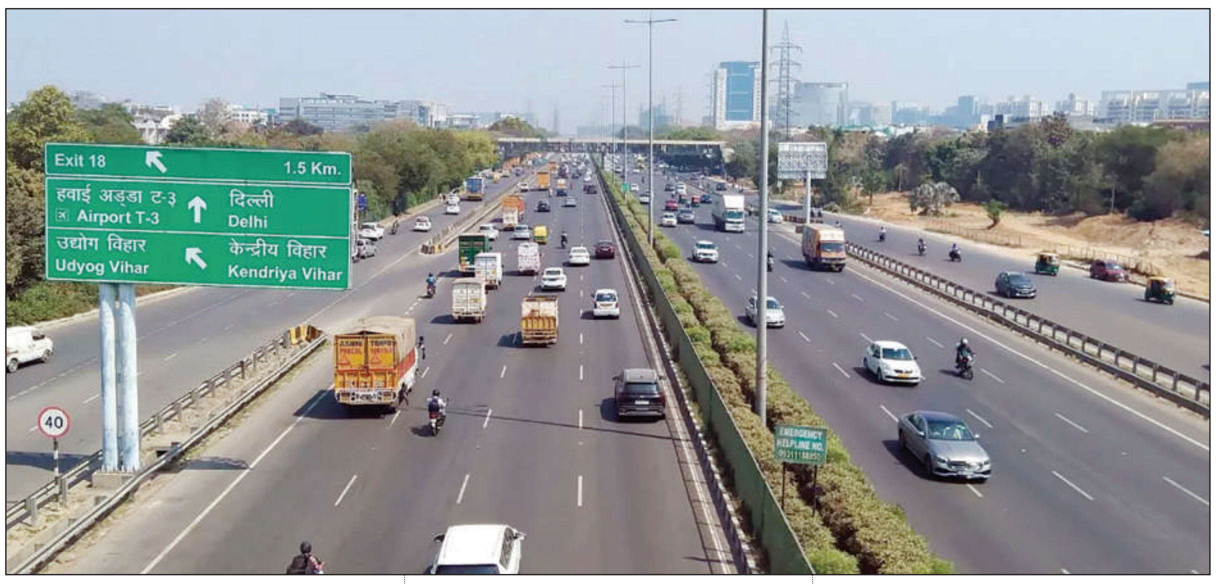

15 से 20 किलोमीटर के अंतराल पर होनी चाहिए सुविधा

हाईवे या एक्सप्रेस-वे पर 15 से 20 किलोमीटर के अंतराल पर अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर की सुविधा होनी चाहिए। उसमें सर्जिकल, आर्थोपेडिक केयर एवं न्यूरो सर्जरी केयर की बेहतर सुविधा होनी चाहिए। एक एंबुलेंस, एक क्रेन एवं फार्मासिस्ट की सुविधा भी होनी चाहिए।

15 से 20 किलोमीटर के अंतराल पर ट्रामा सेंटर की सुविधा होने पर आधे घंटे के भीतर घायल को पहुंचाया जा सकता है। इससे अधिक समय लगने पर खून काफी बह जाता है। फिर गंभीर रूप से घायल को खासकर जिसे सिर में चोट लगी है, बचाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जिन्हें सिर में चोट लगती है, उनमें से अधिकतर की मौत हो जाती है।

दिल्ली के ट्रामा सेंटरों पर एनसीआर का भी बोझ

दिल्ली में अधिकृत ट्रामा सेंटर : 3
कुल बेड क्षमता : 446
एम्स ट्रामा सेंटर : 264 बेड
आरएमएल अस्पताल का ट्रामा सेंटर : 111 बेड
सुश्रुत ट्रामा सेंटर : 71 बेड

सफदरजंग अस्पताल में है सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्लाक

सफदरजंग अस्पताल में एनसीआर का सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्लाक है, जिसकी बेड क्षमता 500 है। हादसा पीड़ितों के लिए भी बेड आरक्षित हैं। एम्स ट्रामा सेंटर के बाद सबसे ज्यादा हादसा पीड़ित सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती होते हैं।

इन दोनों अस्पतालों में एनसीआर के शहरों हादसा पीड़ित इलाज के लिए पहुंचते हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में ट्रामा सेंटरों की संख्या तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ जगहों पर निर्माण चल रहा है। बाहरी दिल्ली के संजय गांधी स्मारक अस्पताल में 362 बेड का ट्रामा सेंटर निर्माणाधीन है, जो जल्द शुरू होगा।

बाहरी दिल्ली में ही जीटी करनाल रोड के नजदीक सिरसपुर में 2716 बेड का अस्पताल बनना है। पहले चरण में अगस्त 2020 से 1164 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है।

दूसरे चरण में 1552 बेड के अस्पताल ब्लाक का निर्माण होगा। इसमें ट्रामा सेंटर भी होगा। हादसा पीड़ितों के बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के इलाके में भी अत्याधुनिक ट्रामा सेंटर होना चाहिए।

जिले	हर साल औसतन मौत
गुरुग्राम	400
फरीदाबाद	250
रेवाड़ी	100
गौतमबुद्ध नगर	700
गाजियाबाद	200
पलवल	250
नूंह	300
सोनीपत	350

हाईवे व एक्सप्रेस-वे बेहतर से बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह अच्छी बात है। देश के विकास के लिए हाईवे व एक्सप्रेस-वे का निर्माण आवश्यक है लेकिन जिसके लिए बना रहे हैं उसकी सुरक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। 15 से 20 किलोमीटर के अंतराल पर ट्रामा सेंटर बनाने पर जोर दिया जाए। दुर्भाग्य है कि कभी भी चुनाव में यह मुद्दा होता ही नहीं। जिंदगी कैसे बचे, यह मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। एनसीआर में हाईवे का जाल बिछा है। इसे ध्यान में रखकर चारों तरफ ट्रामा सेंटर खोलने पर तत्काल प्रभाव से जोर दिया जाए। कहीं भी अधिकतर अस्पताल जिसमें ट्रामा की सुविधा है, वे सड़क से काफी अंदर हैं। ट्रैफिक का दबाव इतना रहता है कि एंबुलेंस के पहुंचने में भी समय लग जाता है। यही वजह है कि अधिकतर लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो जाती है।

- गजेंद्र त्यागी, प्रबंध निदेशक, क्लासिक सिविल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

आखिर कब शुरू होगा वीएलटीडी/ पैनिक बटन निगरानी सेंटर

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली में निर्भया कांड दुर्घटना के साथ ही महिला सुरक्षा को परिवहन में सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, उच्च न्यायालय दिल्ली और दिल्ली सरकार ने बड़ी बड़ी बाते बोली थी पर आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सब कुछ है जीरो (0), आखिर क्या है इसका कारण और कौन है जिम्मेदार? दिल्ली की जनता की आंखो में धूल झोंकने के लिए वाहन मालिकों पर वीएलटीडी/ पैनिक बटन निगरानी के नाम पर शुरु कर दी फीस लेनी पर ना आज तक निगरानी सेंटर बना और ना ही पैनिक बटन खिलौने से ज्यादा काम आए पर इस नाम से **परिवहन विभाग ओर परिवहन विभाग की 50% हिस्सेदारी वाली कम्पनी की हो गई बल्ले बल्ले** वीएलटीडी/ पैनिक बटन निगरानी सेंटर बनाने के लिए परिवहन विभाग को 8 करोड़ रुपए प्राप्त हुए पर उसके बावजूद आज तक नहीं शुरु किया गया निगरानी सेंटर। हमारी जानकारी के अनुसार एनआईसी द्वारा यह निगरानी सेंटर बनाया जाना है और एनआईसी की तरफ़ से एमओयू तैयार हो कर आए भी कई महीने बीत चुके हैं पर इस पर साइन करने के लिए परिवहन विभाग के आला अधिकारी के पास समय नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वह जनहित के अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। उनके लिए दिल्ली के सार्वजनिक सवारी वाहनों में महिला सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी कार्य है :- जैसे जनता के समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों को उठवा कर अपने प्रिय स्क्रैप डीलर को सुपुर्द करवाना, आनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपल्ब्ध होने पर भी हस्तचालित कार्यशैली को हरी झंडी देना, वाहन मालिक अपने समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनो को अन्य राज्यों में ना लें जा पाए उसके लिए एनओसी को रुकवाना, बाहरी राज्यों में पंजीकृत समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों को जब्त कर कानूनन छोड़ने की जगह जब्त करवाकर रखना इत्यादि जनहित के कार्य। वाहनों में लगे **सीसी कैमरे खिलौने, पैनिक बटन खिलौने** और बिना निगरानी सेंटर बनाए खिलौनो की निगरानी के नाम से वाहन मालिको से फीस लेना ही क्या महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना था मुख्य ध्येय?, **बेहतरीन है ना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का यह अनोखा तरीका !!!**

पहले दिन ही दुर्गावती टाइगर रिजर्व ने वापस लिया अपना आदेश, अब रात में गुजर सकेंगे भारी वाहन

रानी दुर्गावती टाइगर पार्क प्रबंधन ने भारी वाहनों के अभयारण्य में रात के समय प्रवेश पर पाबंदी संबंधित अपना आदेश वापस ले लिया है। बस चालकों ने अपनी परेशानी बताई थी। इसके बाद नौरादेही प्रबंधन ने यह कदम उठाया।

नई दिल्ली। रानी दुर्गावती टाईगर रिजर्व के नौरादेही अभयारण्य प्रबंधन ने एक अप्रैल से सूर्यास्त के बाद मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। इस आदेश को पहले ही दिन वापस ले लिया गया है। इसके बाद रात में भी भारी वाहन और चार पहिया वाहन रिजर्व से गुजर सकेंगे।

जैसे ही नियम लागू होने का समय आया, उससे पहले बड़े वाहन मालिकों ने इस संबंध में वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्हें बताया कि यदि बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगता है तो शासन के साथ उन्हें भी हानि पहुंच सकती है। उसके नफे-नुकसान के बारे में बताया। अधिकारियों ने बड़े वाहन मालिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कुछ समय के लिए आदेश को वापस ले लिया है।

यह आदेश जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया था। रात्रि के समय जंगली जानवरों का मुख्य मार्ग पर आवागमन रहता है। ऐसी स्थिति में भारी वाहन इन जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचा दें या फिर कोई जंगली जानवर जैसे बाघ या अन्य जानवर किसी राहगीर को नुकसान न पहुंच सके इसके लिए यह नियम बनाया गया था। फिलहाल इसे टाल दिया गया है।

कई बसों का होता है संचालन

सागर से जबलपुर और सागर से झलौन, दमोह, सर्रा, रहली मार्ग पर दर्जनों यात्री बसों का संचालन होता है। इसके बस मालिकों के पास आरटीओ से उस रुट का परमिट भी है। बस मालिकों को एक अप्रैल से लागू नए नियम की जानकारी लगी तो वह नियम लागू होने के एक दिन पूर्व नौरादेही अभयारण्य के अधिकारियों से मिले और उन्होंने बताया कि यदि मार्ग पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो दर्जनों बसों का आवागमन बंद हो जाएगा। आवागमन के बदले बस मालिक प्रतिमाह शासन को परिवहन विभाग के माध्यम से जो टैक्स अदा करते हैं वह भी बंद हो जाएगा।

पार्क नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़क

बस मालिकों ने यह भी बताया कि जिस मार्ग से उनकी बसों का आवागमन हो रहा है वह टाइगर रिजर्व की नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है। वहां पर यह नियम लागू करना उचित नहीं होगा। बस मालिकों की समस्या के बाद नोरादेही प्रबंधन ने विचार करने के बाद पहले ही दिन इस आदेश को वापस ले लिया।

ग्रामीण भी कर रहे थे विरोध

बस मालिकों के साथ तारादेही मार्ग पर बसे दर्जनों गांव के लोग भी इस आदेश का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि हम लोगों के घरों में आवागमन दिन,रात लगा रहता है। रिश्तेदार आते हैं। विवाह होते हैं। यदि ऐसी स्थिति में यह नियम लागू होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। तेंदूखेड़ा, तारादेही, खमतरा मार्ग से सीधे महराजपुर मार्ग पर दिन-रात आवागमन होता है। नियम लागू होगा तो इस मार्ग पर रहने वाले लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रबंधन के आदेश वापस लेने के बाद बस मालिकों के साथ उन सैकड़ों ग्रामीणों को भी राहत दी है जो एक अप्रेल से परेशान हो सकते थे।

पुराना आदेश स्थगित करने कराया लेख

टाइगर रिजर्व की सीमा में नियम लागू होने का तत्काल प्रचार प्रसार कराया जाता है। पूर्व में ज़ब 1 अप्रैल से आवागमन में प्रतिबंध लगाया जा रहा था तो उसके काफी दिन पूर्व उसका प्रचार प्रसार कराया गया था। लेख कराये गये थे, लेकिन अब वह नियम वापस ले लिया गया है तो उसका भी उसी तरह प्रसार, प्रचार कराया जा रहा है जिस तरीके से नियम लागू करने का कराया गया था। मुहली रेंजर नीरज बिसेन ने बताया कि बस मालिकों की कुछ समस्याओं को लेकर और प्रचार-प्रसार के अभाव के कारण पुराने आदेश को अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है।

अलसुबह बिजबिहाड़ा में गूंजी चिनूक विमान की गूंज, पातकालीन रनवे पर हुआ सफल ट्रायल

परिवहन विशेष न्यूज

जम्मू। बिजबिहाड़ा में अचूक हेलिकॉप्टर चिनूक की धमक ने लोगों को नींद से जगाया। राजमार्ग पर बनाई गई आपातकालीन हवाई पट्टी पर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा रचा गया था। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मंगलवार अलसुबह वायु सेना के विमानों की तेज गड़गड़ाहट ने हुंकार भरी। यहां जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए गए 3.5 किलोमीटर लंबे आपातकालीन रनवे पर वायुसेना ने सफल ट्रायल किया। इस दौरान सुरक्षा और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजमार्ग पर यातायात को भी डायवर्ट किया गया था। बिजबिहाड़ा में अचूक हेलिकॉप्टर चिनूक की धमक ने लोगों को नींद से जगाया। सूत्रों के अनुसार, सुबह 03:45 से 04:30 बजे तक ट्रायल हुआ। राजमार्ग पर बनाई गई आपातकालीन हवाई पट्टी पर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा रचा गया था। भारतीय वायु सेना द्वारा संचालित चिनूक हेलीकॉप्टर एक बहुमुखी भारी-लिफ्ट विमान है जो सैन्य परिवहन, आपदा राहत और रसद सहायता सहित विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 119 करोड़ रुपये की लागत से हवाई पट्टी का निर्माण 2020 में हुआ था। इस पट्टी का उपयोग रणनीतिक उद्देश्यों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा।

हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा होगी महंगी, किराए में कितनी होगी बढ़ोतरी

पिछले साल हुई केदारनाथ यात्रा में 1.50 लाख से अधिक तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे थे. पिछले यात्रा सीजन में पवन हंस, कैट्रल एविएशन, हिमालयन हेली, एयरो एविएशन समेत अन्य कंपनियों से हेली सेवा का संचालन किया था. वहीं टिकटों की मारामारी ना हो इसके लिए पिछले साल की तरह टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की जाएगी.

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रदेश का विकास यहां के तीथस्थलों पर भी निर्भर करता है. यहां की अर्थव्यवस्था में कई अधिक योगदान पर्यटन क्षेत्र से आता है. वही राज्य में देश भर से हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते है. चारधाम यात्रा के लिए सभी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ यहां दर्शन के लिए पहुंचते है. इस वर्ष के लिए भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है ऐसे में कई श्रद्धालु इनकी पूरी जानकारी ले रहे है.

चारधामों में सबसे ज्यादा उत्साह हमेशा से श्रद्धालुओं के बीच देवों के देव महादेव केदारनाथ धाम के दर्शन को ज्यादा उत्सुकता रहती है. इस वर्ष 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई है. बद्री केदार समिति की ओर से श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए पूरी तैयारी करी जा रही है.

इस वर्ष केदारनाथ हेली सेवा के किराये में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. केदारनाथ के कपाट खुलने के दिन से ही सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी से हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा. उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ हेली सेवा के संचालन के लिए एविएशन कंपनियों के साथ तीन साल का अनुबंध किया है. अनुबंध की शर्तों के अनुसार, इस बार हेली कंपनियां किराये में पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी करेगी.

पिछले साल हुई केदारनाथ यात्रा में 1.50 लाख से अधिक तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे थे. पिछले यात्रा सीजन में पवन हंस, कैट्रल एविएशन, हिमालयन हेली, एयरो एविएशन समेत अन्य कंपनियों से हेली सेवा का संचालन किया था. वहीं टिकटों की मारामारी ना हो इसके लिए पिछले साल की तरह टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की जाएगी.

अगर आप भी हेली सेवा के माध्यम से यात्रा की सोच रहे है तो सबसे पहले अपना पंजीकरण जरूर कराएं. हेली सेवा की बुकिंग के लिए यात्रा पंजीकरण अनिवार्य है. साथ ही एक बार में एक व्यक्ति अपनी आईडी से अधिकतम छह सीटों की बुकिंग कर सकेगा, जबकि समूह में यात्रा करने वाले यात्री एक बार में 12 सीट बुक कर सकते हैं।

क्या है साड़ी कैंसर और क्या है इसके बचाव, जाने

आज हम वो बात बताने जा रहे हैं, जिसका अंदाजा आपको एकदम नहीं होगा, लेकिन रोजाना के उपयोग में लाई जा रही साड़ी से एक लंबी बीमारी और कभी न ठीक होने वाला कैंसर भी हो सकता है। भारत में महिलाएं बेहद शान से पांच से छह मीटर लंबी साड़ी पहनने पर गर्व करती हैं। लेकिन, किसी को ये नहीं मालूम कि इससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में आप ये जानिए कि अगर आप कपड़े यानी साड़ी सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपको सीधे तौर पर कैंसर हो सकता है। साड़ी कैंसर अक्सर भारतीय महिलाओं को ही होता है क्योंकि यहां पर महिलाएं साड़ी पहनती हैं। कई महिलाएं इसे 12 महीने और सातों दिन पहनती हैं। साड़ी को पहनने से पहले महिलाएं सूती का पेट्टीकोट भी पहनती हैं, जो उनकी कमर को कई हद तक कस देता है। अब इसपर पीआरएसआई अस्पताल, दिल्ली के कैंसर सर्जन डॉ. विवेक गुप्ता के अनुसार, अगर कोई महिला एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनती हैं, तो उनकी कमर में रगड़ खाने लगती है और इससे त्वचा छील जाती है और कमर में काले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके साथ ही यह एक तरह की साइकिल शुरू हो जाती है, जिससे धब्बे, छीलन पैदा हो जाती है और इससे कैंसर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन, डॉक्टर के मुताबिक अगर आपने स्वच्छता बरकरार रखी, तो आपको इससे निजात मिल जाएगी और आप कभी भी इसके शिकार नहीं होंगे। साड़ी पहनने पर जहां-जहां ज्यादा गर्मी और नमी होती है, वहां कैंसर के बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। इस तरह के केस अभी तक बिहार और झारखंड में दर्ज किए गए हैं। अभी भारत में साड़ी कैंसर के मामले मात्र एक फीसदी है। इसे मेडिकली भाषा में 'त्वचा कोशिकाओं का कार्सिनोमा' माना जाता है। इस पर रिसर्च मुंबई के आरएन कूपर अस्पताल में हुई है। इस रिसर्च में धोती को शामिल कर उसपर भी अपनी अनवेषण किया गया। इस तरह से साड़ी कैंसर का नाम बॉम्बे अस्पताल के द्वारा दिया गया, यह तब दिया गया जब 68 वर्षीय महिला को साड़ी कैंसर हुआ था। वह महिला पिछले 13 साल से साड़ी पहन रही है।

यूपी की बिटिया के लिए सरकारी स्कीम: पहले बर्थडे से पहले करवा लें रजिस्ट्रेशन, 2 लाख रु मिलेंगे, भाग्य लक्ष्मी योजना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में बेटियों के लिए एक ऐसी स्कीम चलाई हुई है जिसका लाभ वह हर शख्स ले सकता है जो इसके नियमों को पूरा करता हो. यूपी सरकार की इस स्कीम का नाम है भाग्य लक्ष्मी योजना. इसकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसे केवल वे ही परिवार अपनी बेटी के लिए अवेल कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम हो. साथ ही जिस बच्ची के लिए आपको ये सुविधा या मदद लेनी है उसके पहले बर्थडे से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा. महिलाओं और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप यहां क्लिक कर सकती हैं.

भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत यूपी सरकार बच्ची के जन्म के समय पचास हजार रुपये का बॉन्ड देती है. ये बॉन्ड बच्ची के 21वें जन्मदिन पर 2 लाख रुपये की मच्योरिटी देता है. बच्ची के जन्म के समय मां को 51 सौ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. सरकार भ्रूण हत्या को रोकने, बच्ची की शिक्षा के लिए ये रकम देती है. बच्ची की पढ़ाई के लिए कुल 23 हजार रुपये की मदद मिलती है. यह वित्तीय सहायता एकमुश्त नहीं होती बल्कि यह किस्तों में मिलती है. यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाता है. वैसे ये एक ही परिवार में जन्मी अधिकतम दो बच्चियों को ही लाभ दिया जाता है. इससे ज्यादा बेटियां हुईं तो उनके नाम पर यह मदद नहीं मिलती है. इस योजना के बारे में और अधिक सरकारी जानकारी के लिए इस पते पर लॉगइन करें- https://mahilakalyan.up.nic.in/

बिना ब्याज के मिल रहा 5 लाख रुपये तक का लोन, महिलाओं को लखपति बनाने की पहल,

पांच सरकारी योजनाएं जो पूरे देश में हैं लागू, बहनों-बेटियों को देती हैं उड़ने के लिए आसमान

लाडली बहन योजनाः 21 साल से अधिक आयु है तो ले सकती हैं लाभ, मगर एक बड़ी शर्त

बच्ची की पढ़ाई के लिए जो राशि दी जाती है वह चरणों में दी जाती है, कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि, 8वीं क्लास में प्रवेश लेने पर बच्ची को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता और इंटर यानी 10वीं में प्रवेश लेने पर बेटी को 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है. बता दें कि ये लाभ केवल यूपी के निवासी के लिए है. इसमें माता-पिता और बच्ची का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्ची का बर्थ सार्टिफिकेट, इनकम सार्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अड्रेस प्रूफ, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज चाहिए.

आप इसके लिए केवल ऑफलाइन अप्लाई कर सकती हैं- https://mahilakalyan.up.nic.in/ पर लॉगइन करने के बाद भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकालें और सही सही जानकारी भर दें. उपरोक्त दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाकर जमा कर दें।

दुनिया की इन 4 जगहों पर महीनों नहीं डूबता है सूरज, जानिए इनके बारे में

दुनिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में जानकर आश्चर्य होता है। हम ऐसे ही एक आश्चर्य के बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर सूरज नहीं डूबता है। आप ये जानकर हैरान हो गए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि जहां सूरज नहीं डूबता वहां रात कैसे होती होगी। वहां रहने वाले लोगों को पता कैसे चलता होगा कि दिन कब हुआ और रात कब हुई। चलिए हम आपको इन जगहों के बारे में बताते हैं।

नॉर्वे नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां सूरज जल्दी नहीं डूबता है। यूरोप के उत्तर में स्थित नॉर्वे देश की जलवायु समशीतोष्ण है। यहां सूरज बहुत देर में अस्त होता है।

नुनावुत, कनाडा आर्कटिक सर्कल से दो डिग्री ऊपर स्थित उत्तरी कनाडा की जनसंख्या दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। यहां पर महज 3000 हजार लोग रहते हैं। इसे दुनिया में सबसे ठंडी जगह कहा जाता है। इस देश में साल में 60 दिन तक सूरज नहीं डूबता है। पर सर्दियों में 30 दिन तक अंधेरा रहता है।

स्वीडन यूरोप का देश स्वीडन चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। यहां मई से लेकर अगस्त तक सूरज करीब 12 बजे डूबता है और सुबह 4.30 बजे उगता है। यहां पर 6 महीने तक हमेशा सुबह रहती है।

आइसलैंड आइसलैंड एक द्वीप देश है, जो उत्तरी यूरोप में अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस देश में सूरज जल्दी नहीं डूबता है। यहां सर्दियां काफी समय के लिए रहती हैं और गर्मियां बहुत कम समय के लिए रहती हैं।

हर व्यक्ति अपनी हेल्थ पॉलिसी को पोर्ट कर रहा है, क्या आपको भी ऐसा करना चाहिये?

Health Insurance हम सभी के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अपने हेल्थ इंश्योरेंस को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करवा सकता है। आज के समय में कई लोग हेल्थ पॉलिसी को पोर्ट करवा रहे हैं। दरअसल कभी किसी कंपनी की सर्विस पसंद ना आने पर ग्राहक यह कदम उठाते हैं। आइए जानते हैं कि क्या आपको भी हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट करना चाहिए।

नई दिल्ली। आप जब भी किसी उत्पाद या सेवा में निवेश करते हैं, तब सुनिश्चित करते हैं कि वह लंबी अवधि में अधिकतम लाभ प्रदान करे। लंबी अवधि के लिये लाभ को अधिकतम बनाने में शामिल है तात्कालिक फायदे से आगे की सोचना; मतलब ऐसा मूल्य चुना, जो टिका रहे और भविष्य में भी लाभ देता रहे। यह दृष्टिकोण न सिर्फ हमारे आम वित्तीय निवेशों पर, बल्कि स्वास्थ्य बीमा पर भी लागू होता है।

आज की दुनिया में जब इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य बीमा में निवेश करना एक जरूरत है। इसके अलावा, कोविड-19 के प्रकोप ने स्वास्थ्य बीमा के महत्व पर जागरूकता पैदा की है और पर्याप्त सुरक्षा, बेहतर खूबियों तथा सेवाओं की जरूरत समझाई है। इस समझ के चलते कई लोग अपनी पॉलिसी को पोर्ट भी कर रहे हैं।

स्वास्थ्य बीमा एक चिकित्सीय आपातकाल में पॉलिसीधारक के लिये तात्कालिक आर्थिक सहयोग का आश्वासन देता है। हालांकि पॉलिसी की खूबियों में कमी, मूल्य और बीमाकर्ता की सेवाएं अक्सर पॉलिसीधारक को मुश्किल हालात में डाल देते हैं। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी बचाव का काम करती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई) ने 2011 में ऐसे लोगों के लिये हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी पेश की थी, जो अपने बीमाकर्ता द्वारा प्रदत्त सेवा या सुरक्षा से संतुष्ट नहीं थे।

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के साथ आप पॉलिसी के मौजूदा लाभों से वंचित हुए बिना आसानी से पॉलिसी को एक बीमाकर्ता से दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं। बाजार में उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा के कई विकल्पों को देखते हुए, सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी को चुनना एक कठिन काम हो सकता है।

आपको नये बीमाकर्ता के साथ तभी पोर्ट करना चाहिये, जब नई पॉलिसी आकर्षक लाभ दे और स्वास्थ्य की उन जरूरतों को पूरा कर सके, जिन्हें मौजूद पॉलिसी पूरा नहीं कर सकती है। नई पॉलिसी की बीमित राशि में मौजूद पॉलिसी का बोनस जोड़ देने से नई पॉलिसी का महत्व बढ़ सकता है। इस लेख में स्वास्थ्य बीमा की पोर्टिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का गहराई से पता लगाया गया है।

हेल थ इंश योरेंस को कैसे पोर्ट करें?

हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट करते समय आपको सुनिश्चित करना चाहिये कि आपके प्लान में इन्डेम्निटी (क्षतिपूर्ति) कवर हो, जिसमें एक पक्ष दूसरे के व्यय हुए नुकसान के लिये मुआवजा दे।

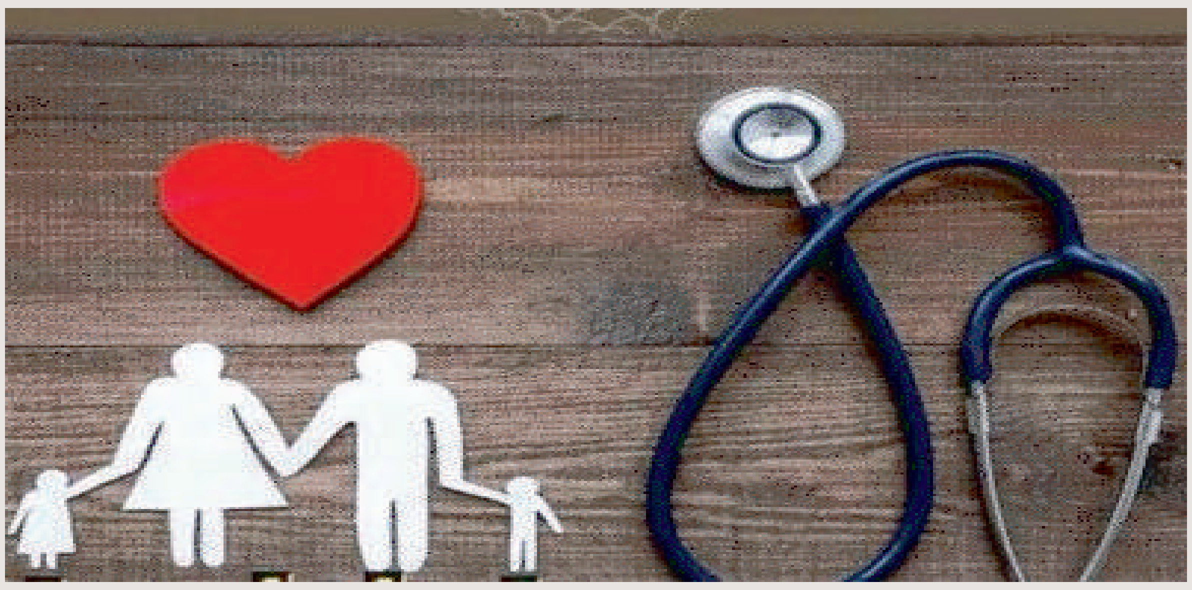

इसके अलावा, आपको मौजूदा पॉलिसी की समाप्ति के कम से कम 45 दिन पहले पॉलिसी पोर्टिंग के बारे में मौजूदा बीमा कंपनी को बताना चाहिये। ज्यादातर बीमा पॉलिसी नवीकरण के समय पॉलिसीधारकों को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट करने की अनुमति देते हैं।

अगर आपकी मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यक प्रतीक्षा अवधि पूरी हो चुकी है, तो आप पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हैं। कुछ बीमा प्रदाता पॉलिसीधारकों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट करने की अनुमति देते हैं, अगर उन्होंने एक विशेष अवधि के दौरान कोई दावा न किया हो। पॉलिसी को पोर्ट करने के लिये आपके चयनित बीमा प्रदाता द्वारा समान प्रकार की सुरक्षा दी जानी चाहिये।

इंश योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करने के चरण

आईआरडीए पोर्टेबिलिटी फॉर्म भरें, यह आपकी पॉलिसी के नवीकरण से पहले किया जा सकता है।

नये बीमाकर्ता से संपर्क करें, जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। फिर आप विभिन्न प्रकार के हेल्थ प्लान्स को साझा करेंगे।

एक प्लान चुनें और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करें। फिर वे मेडिकल रिकॉर्ड के लिये आपके पिछले बीमाकर्ता से संपर्क करेंगे।

आपके द्वारा इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी फॉर्म समेत सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आपके नये बीमाकर्ता को 15 दिनों के भीतर प्रस्ताव स्वीकार करना होगा।

प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद आपको नई पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

क या आपको अपना हेल थ इंश योरेन्स पोर्ट करना चाहिये?

हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट करने के कई फायदे और नुकसान होते हैं। सकारात्मक तरीके से, हेल्थ इंश्योरेंस को पोर्ट करने का एक बड़ा फायदा है प्रतिस्पर्द्धी दामों पर ज्यादा सुरक्षा जोड़कर और बेहतर खूबियाँ लेकर अपने प्लान को अपग्रेड करने की योग्यता। यह विकल्प कस्टमाइजेशन की अनुमति देता है और सुनिश्चित करता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपकी ही आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसके अलावा, पोर्टिंग की प्रक्रिया में आपके मौजूदा प्लान के सभी फायदे वैसे ही बने रहेंगे। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पोर्टेबिलिटी के विकल्प आमतौर पर नवीनीकरण की तारीख आने के साथ उपलब्ध होते हैं और आपके पास बदलाव के लिये सीमित समय होता है। इसके अलावा, अतिरिक्त फायदों वाला एक नया प्लान चुनते समय यह देखना महत्वपूर्ण है कि यह फायदे प्रीमियम को बढ़ा सकते हैं। फिर, अगर आप ग्रुप प्लान्स से इंडिविजुअल प्लान्स में जा रहे हैं, तो मौजूदा प्लान में आप जिन फायदों का लाभ उठा रहे हैं, वो खो सकते हैं।

निष्कर्ष

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी को लेकर कई तर्क हैं, लेकिन पोर्टेबिलिटी की जरूरत को सावधानी से समझना महत्वपूर्ण होता है। आपको बीमा कंपनियों के बीच अंतर वाले हामीदारी के नियम, योजना के बहिष्करण, नियम और शर्तें देखनी चाहिये। नई पोर्ट हुई बीमा योजना से जुड़े नये नियमों और शर्तों को समझना भी जरूरी है। सूचित फैसले लेकर और संभावित फायदों तथा कमियों को समझकर आप स्वास्थ्य बीमा से मिल सकने वाली अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ संभव खूबियां तथा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(लेखक: श्री आशीष लाथ इंश योरेन्सदेखो के बिजनेस हेड हैं)

हेल्थ के लिए बेस्ट हैं ये मुद्राएं, महिलाएं रोजाना करें

बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हेल्दी फूड्स के साथ-साथ एक्सरसाइज पर भी ध्यान दिया जाए। इसलिए हम आपको कुछ मुद्राओं के नाम बता रहे हैं, जिन्हें नियमित रूप से किया जा सकता है।

पिछले महीने तो सारे टेस्ट करवाए थे...पर पता नहीं क्यों फिर से सिर दर्द होने लगा है...कमर में दर्द भी बढ़ गया है..समझ ही नहीं आ रहा कि कौन-सी दवाई खाई जाए....। अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि टेस्ट करवाने के साथ-साथ हेल्दी फूड्स अपने आहार में शामिल करें। साथ ही नियमित रूप से योग करें क्योंकि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज काफी उपयोगी मानी जाती है।

पर बढ़ती उम्र के साथ एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हम आपके लिए कुछ ऐसी मुद्राएं लेकर आए हैं, जिनकी मदद से कई शारीरिक समस्याओं को कम किया जा सकता है। तो आइए एक्सपर्ट हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट स्मृति द्वारा बताई गई मुद्राएं साझा कर रहे हैं। बता दें कि स्मृति खुद का हेल्थ सेंटर चलाती हैं और आए दिन अपने इंस्टाग्राम पर हेल्थ से संबंधित जानकारी साझा करती रहती हैं।

महिलाएं करें पद्मासन

पद्मासन दो शब्दों पद्म यानी कमल और आसन यानी बैठने की मुद्रा से मिलकर बना है। बता दें कि आसान शब्दों में कहें तो कमल की मुद्रा में बैठकर ध्यान करना पद्मासन कहलाता है। इस योग को करने से मानसिक तनाव में बहुत राहत मिलता है।

पद्मासन कैसे करें?

सबसे पहले समतल भूमि पर योग मैट बिछाएं।

कुछ देर इस प्राणायाम मुद्रा में बैठे रहें। (महिलाओं के लिए लाभदायक है पद्मासन)

अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख नाक के अग्र भाग पर फोकस करें।

कुछ पल बाद अपनी आंखें बंद करें।

अब सामान्य तरह से सांसें लें और छोड़ें।

इस योग को रोजाना करें। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और दिमाग शांत रहता है।

30 साल के बाद करें काली मुद्रा

हेल्थ को बनाए रखने के लिए काली मुद्रा करना अच्छी मानी जाती है। आपको किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे योद्धा मुद्रा के नियमित अभ्यास से कर सकते हैं।

मगर इस मुद्रा का लाभ तभी मिलेगा, जब इसको सही ढंग से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस मुद्रा को कैसे किया जा सकता है।

काली मुद्रा कैसे करें?

इस मुद्रा को करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होगी।

इसे करने के लिए तर्जनी मध्यमा, अनामिका और छोटी उंगलियों को आपस में जोड़ें।

फिर ऊपर की ओर इशारा करते हुए इस मुद्रा को करें। (अनामिका उंगली बताती है धन कमाने का तरीका)

ध्यान रखें कि बायां अंगूठा दाहिनी ओर क्रॉस किया जाना चाहिए।

महिलाओं के लिए योनि मुद्रा

आप नियमित रूप से योनि मुद्रा करें। इसे करने से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सुधार के लिए इस मुद्रा को किया जा सकता है। पर कहा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी का सामना कर रहे लोगों को इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। साथ ही, इस मुद्रा को हमेशा शांत वातावरण में करें।

योनि मुद्रा कैसे करें

इसे करने के लिए सुखासन में बैठ जाएं।

अब अंगूठे और तर्जनी को छोड़कर सभी उंगलियों को आपस में फंसा लें।

तर्जनी और अंगूठे को एक साथ लाएं।

पेट पर एक त्रिभुज बनाएं और उंगलियों को नीचे की ओर रखें।

अब आंखें बंद कर लें।

सुनीता केजरीवाल के मोर्चा संभालते ही, बीजेपी ने बदली रणनीति, बांसुरी स्वराज को लाए सामने

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली। दिल्ली के पल-पल बदलते राजनीतिक मल्लयुद्ध के बीच आम आदमी पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल के संभालते ही बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए महिला शक्ति का प्रतिवार ढूंढ लिया है।

आम आदमी पार्टी को सुनीता केजरीवाल के रूप में कदावार महिला चेहरा मिल गया है।तो वहीं अब भाजपा भी अपनी बदलती रणनीति के तहत महिला नेताओ से काउंटर अटैक कराने के मूड में है।इसी के तहत प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज को सुनीता केजरीवाल का कांउटर अटैक करने के लिए मैदान में उतार दिया है।बता दें कि भाजपा आलाकमान भी इसी रणनीति को लोकसभा चुनावी अभियान के दौरान जारी रखने की नीति पर आगे बढने/कदमताल का संकेत दिया है।उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा के दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने भी दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को दिवंगत केंद्रीय मंत्री व दिल्ली सीएम रहीं सुषमा स्वराज के खिलाफ बतौर भाजपा का चेहरा पेश किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को उतार कर सहानुभूति कार्ड खेल रही है। शुरू में तो आप ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिषी को आगे किया था।अब रणनीति बदलते हुए खुद मैदान में मुख्यमंत्री की पत्नि उतर गई है।

इस कार्ड के काट के रूप में भाजपा के रणनीतिकारों ने महिला ब्रिगेड को आगे करने की मुहिम में है। भाजपा शुरू से आम आदमी पार्टी की सरकार पर दिल्ली दिल्ली कैबिनेट में महिलाओ के प्रतिनिधित्व को लेकर आवाज भी उठाती रही है। हालांकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसौदिया के जेल जाने के बाद आतिशी को कैबिनेट में शामिल किया गया।अब जब सुनीता केजरीवाल जब दिल्ली की राजनीति में कूद पडी हैं तो भाजपा की नीति में भी बदलाव दिखने लगा है। वहीं इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर राजनीतिक गलियारों में वार- प्रतिवार का सिलसिला लगातार जारी है। बांसुरी स्वराज ने सोमवार को सुनीता केजरीवाल से सवाल किया कि बताए क्या वह अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है? क्योकि अब सुनीता वही केजरीवाल की सरकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल प्रेस संदेश देने में कर रही है? आप कहना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली है। जबकि कांग्रेस का दावा है कि यह रैली किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की कुर्सी की लडाई महिला बेस आधारित रही हैं। शीला दीक्षित के खिलाफ 25 साल पहले 1999 में सुषमा स्वराज के विकल्प के तौर पर स्थापित किया था। सुषमा स्वराज भी दिल्ली की मुख्यमंत्री के बतौर बेहतर जिम्मेदारी निभा रही थी। लेकिन तब 40 रूपये किलो में बिके प्याज की मंहगाई की मार ने भाजपा को चुनाव में हार का मुंह देखना पडा था। 1999 से लगातार भाजपा दिल्ली की गद्दी पर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी चक्कर में भाजपा ने आम आदमी पार्टी के हाथों दिल्ली नगर निगम को भी गंवा दिया है। दिया है।

गर्मी की बीमारियों में कारगर है होम्योपैथिक उपचार- डा. वर्मा

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जिला चिकित्सालय के आयुष चिकित्साधिकारी डा. वी.के. वर्मा ने गर्मी के मौसम में लोगों को बचाव की जानकारी दी। डा. वर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में भूख गायब हो जाती है और दिन भर कुछ लोगों को बस प्यास ही सताती है। गर्मी में पेट और पाचन से जुड़ी समस्याएं सबसे ज्यादा होती है. जरा सी लापरवाही से उल्टी-दस्त की समस्या होने लगती है. इसीलिए आपको गर्मी में दिनचर्या और खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए।खुली जगह में विश्राम न करें, सिर पर सफेद गीले कपड़े की पूरे सिर की पगड़ी, रूमाल बांधकर रहे सूखने पर गीला रखे पूरे शरीर पर सफेद, हल्के रंग के कपड़े पूरी बोह तक के ढीले वस्त्र पहने आँखों पर धूप का चश्मा, छतरी हैट का प्रयोग करें। पानी का सेवन अधिक से अधिक करें (5 लीटर से 8 लीटर) प्रति दिन शुद्ध पेयजल (जमीनी जल) छाछ, पना, जलजीरा, नीबू नमक, पानी आदि का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। यात्रा करते समय पर्याप्त मात्रा में पानी रखें। शराब चाय, काफी, एवं साफ्ट ड्रिंक्स का उपयोग न करें, मांसाहारी खाना न खाये, हल्का फुल्का भोजन करें। अगर कुछ असुविधा महसूस करे तो तुरन्त डाक्टर से सलाह लें।

डा. वर्मा ने बताया कि होम्योपैथिक उपचार तेजी से दर्द, गति उपचार, और संक्रमण को रोकने के लिए काम करते हैं. इसके अलावा होम्योपैथिक उपचार सुरक्षित, और साइड इफेक्ट्स के बिना हैं। बेलाडोना, एकोनाइट, ग्लोनायन,, कैंथरिस, फेरम फॉस, कैलेंडुला, अर्नीका, कार्वो वेज, लाइको, इपिकाक, मैग फॉस, चाइना, नक्स वाम, आदि होम्योपैथिक दवायें गर्मी के दिनों में कारगर है। मरीजों को चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका प्रयोग करना चाहिये।

'हम जश्न नहीं मना रहे': संजय सिंह ILBS अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों ने की बायोप्सी; बुधवार को पहुंच सकते हैं घर

परिवहन विशेष न्यूज

सुप्रीम कोर्ट से जमानत की खबर सुनने के बाद संजय सिंह के समर्थक ढोल के साथ उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह को शुभकामनाएं दीं।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह करीब छह माह बाद बुधवार को घर लौट सकते हैं। फिलहाल, लिवर से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए वे लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में लिवर की बायोप्सी की गई है। इस जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज होगा।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत की खबर सुनने के बाद संजय सिंह के समर्थक ढोल के साथ उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह को शुभकामनाएं दीं। पत्नी ने कहा कि यह संघर्ष लंबा है और आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन जेल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। संजय सिंह के बाहर आने का हम जश्न नहीं मना रहे हैं। जमानत के लिए हम अदालत को धन्यवाद देते हैं। संभावना है कि संजय बुधवार को घर आ जाएंगे।

सुनीता केजरीवाल से मिले आप विधायक-पार्षद, बोलीं- जेल से चलेगी सरकार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक व पार्षद पहली बार सुनीता केजरीवाल से मिले। मुख्यमंत्री आवास पर इस दौरान सभी ने दावा किया कि दिल्ली सरकार जेल से चलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है।

इस दौरान सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल के साथ एकजुट खड़े रहने का दावा किया। साथ ही कहा कि दिल्ली की दो करोड़ जनता उसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए। भाजपा तो चाहती है कि वह इस्तीफा दें। इसके लिए भाजपा कैंपेन भी चलाएगी, लेकिन जब वो इस्तीफा दे देंगे तो यही भाजपा कहेगी कि वो भाग गए। सुनीता केजरीवाल विधायकों का यह संदेश अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाएगी।

बैठक के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब दो दर्जन विधायकों ने अपनी बात सुनीता केजरीवाल के सामने रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस्तीफे के लिए अभियान चलाएगी। इससे पहले लोकपाल बिल के समय पर जब वो पास नहीं हो पाया था, तब सीएम पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया था। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कहा गया कि वो भाग गए।

विधायकों के बाद पार्षदों से मिली सुनीता

मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों के बाद आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद पहुंचे। सभी पार्षदों ने कहा कि वें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। इस संकट के घड़ी में पार्षद आप के साथ खड़े हैं और भाजपा की कोशिश पूरी नहीं होने देंगे।

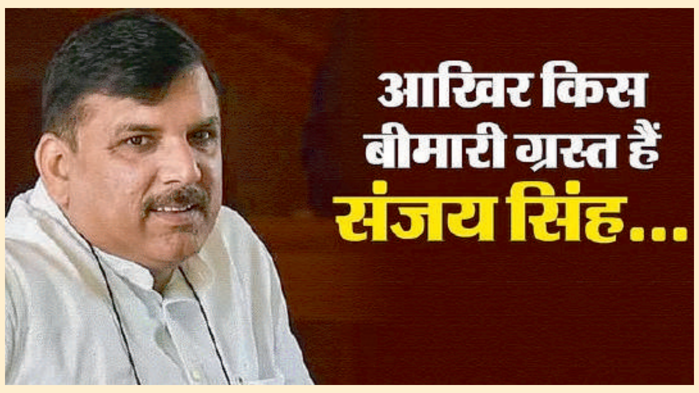

जेल की सलाखें बढ़ाएगी भाजपा की मुश्किल: केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि जेल की सलाखें भाजपा के लिए मुश्किल बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि ये बात हम सबको समझ आ रही है कि जब तक जेल में रहेंगे, भाजपा के लिए मुश्किलें और बढ़ती जाएंगी। दरअसल सुनीता केजरीवाल के माध्यम से सीएम केजरीवाल ने जेल से आप के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संदेश भेजा है। इसमें कहा कि मेरी चिंता न करें। मैं ठीक हूं, मजबूत हूं और मेरे इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हैं। सीएम केजरीवाल को इस बात पर गर्व है कि उनके जाने के बाद भी उनके विधायकों, पार्षदों और संगठन के लोगों ने मिलकर रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया।

भाजपा के लिए सत्ता दूर: सौरभ भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में सत्ता हासिल करने का सपना देख रही भाजपा को अभी लंबा इंतजार करना होगा। पिछले 25 सालों भाजपा इसी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ। आने वाले दिनों में भी यह सपना पूरा होना आसान नहीं है।

'आप ने सीएम केजरीवाल के जरिए की मनी लॉनड्रिंग', ईडी ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिया जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ईडी ने कहा कि शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ आप को मिला। इन पैसों में से लगभग 45 करोड़ रुपयों का उपयोग आप ने गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान चुनाव अभियान में किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अपना जवाब पेश किया है। सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने सीएम केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉनड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आप ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉनड्रिंग की है और यह अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। साथ ही ईडी की ओर से दायर जवाब में कहा गया कि आम आदमी पार्टी (आप) को शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ मिला। इन पैसों में से लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आप के चुनाव अभियान में किया गया है।

कुत्तों की 23 नस्लों पर बैन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई, कोर्ट ने कहा- ये बहुत क्रूर

परिवहन विशेष न्यूज

23 नस्लों के खूंखार कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि ये बहुत क्रूर कुत्ते हैं और वे बच्चों का पीछा कर रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 23 नस्लों के खूंखार कुत्तों की बिक्री और प्रजनन पर केंद्र के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं अपने पास स्थानांतरित कर लीं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि ये बहुत क्रूर कुत्ते हैं और वे बच्चों का पीछा कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि एक बार जब खंडपीठ मामले को देख लेगी तो एकल न्यायाधीशों के समक्ष लंबित अन्य सभी समान याचिकाएं भी उसके पास आएंगी और एक साथ सुनवाई की जाएंगी।

कोर्ट ने कहा कि एक बार जब डिविजन बेंच मामले को अपने कब्जे में ले लेती है तो ऐसे सभी मामले यहां आने चाहिए। वास्तव में सभी एकल न्यायाधीशों को अपने संबंधित मामले यहां भेजने होंगे। हम मामले की फाइलों को यहां तलब करेंगे। आप अन्य लंबित जनहित याचिका में एक पक्षकार आवेदन दायर करें और हम आपकी बात सुनेंगे। हम इस पर इतनी सारी जनहित याचिकाएं नहीं रख सकते। पीठ ने कहा और कहा कि एक ही मुद्दे पर कई याचिकाएं केवल जटिलताएं पैदा करेंगी और मामले के निपटारे में देरी करेंगी।

पेट लवर्स एसोसिएशन ने केंद्र की 12 मार्च की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी थी कि हितधारकों से परामर्श या आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए बिना 23 कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर पीठ ने कहा, 'हर कुत्ते प्रेमी या कुत्ते के मालिक या एसोसिएशन को एक पक्ष बनाकर नहीं सुना जा सकता, यह असंभव है। यह हमारे निर्देश पर हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम केंद्र सरकार को जांच करने का निर्देश दें और फिर हम कहें कि केंद्र सरकार ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती। हम इसे देखेंगे और जांच करेंगे।'

खंडपीठ ने कहा कि उसने पहले ही इसी तरह की जनहित याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और मौजूदा याचिका का निपटारा कर दिया है, जिससे याचिकाकर्ता संगठन को उस मामले में पक्षकार या हस्तक्षेप आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता मिल गई है। पीठ ने इसी मुद्दे पर एकल न्यायाधीशों के समक्ष लंबित याचिकाओं को भी अपने पास स्थानांतरित कर लिया और मामले को नौ अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

आतिशी के दावे पर BJP का पलटवार: 'हमारे यहां आतिशी के लिए वैकेंसी नहीं, हम उन्हें लेकर सिरदर्दी नहीं ले सकते'

परिवहन विशेष न्यूज

आतिशी ने अपने दावे में कहा था कि भाजपा ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार करते हुए कहा कि 'हमारे यहां आतिशी जैसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है'।

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है। उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचा के रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाएं। उनके इस दावे पर भाजपा ने भी पलटवार किया।

भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आतिशी के दावे को लेकर कहा कि 'हमारे यहां आतिशी जैसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे समय जब शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, तो उन्हें अपने यहां लेकर क्या हमें सिरदर्दी लेनी है'।

#WATCH दिल्ली: AAP नेता

> आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि ईडी मेरे घर पर छापेमारी कर सकती है और आने वाले दिनों में मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सौरभ और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे।

आतिशी के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ₹हमारे यहां आतिशी जैसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है...ऐसे समय जब शराब घोटाले में सारी आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, ऐसे समय उन्हें अपने यहां लेकर क्या हमें सिरदर्दी लेनी है... pic.twitter.com/eUTLllYJpy

आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि ईडी मेरे घर पर छापेमारी कर सकती है और आने वाले दिनों में मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सौरभ और राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देंगे।

आतिशी ने आगे कहा है कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी को बोला है कि भाजपा में शामिल हो जाएं, अन्यथा उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें मालूम हुआ कि भाजपा आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। इस कड़ी में उनके साथ-साथ सौरव भारद्वाज, राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। उनके घरों पर भी रेड की जाएगी और फिर समन भेज कर तलब किया जाएगा। उस दौरान उन्हें गिरफ्तार करने की योजना है।

संजय सिंह की जमानत पर पत्नी अनीता बोलीं: हम लोग जश्न नहीं मनाएंगे, देश की जनता सब देख रही

छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश मंगलवार को दिया गया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। वहीं जमानत के बाद संजय सिंह की पत्नी ने कहा है कि अभी वह खुशी नहीं मनाएंगी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आखिरकार दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत मिल गई। वह करीब पिछले छह महीनों से जेल में बंद थे। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी अनीता सिंह का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि हम सभी अभी खुशी नहीं मनाएंगे। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है।

अनीता सिंह से जब संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद पूछा गया कि कितनी खुशी है तो उन्होंने कहा कि अभी खुशी हमारी अधूरी है। अभी हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि हमारे तीन बड़े भाई, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अभी जेल में हैं। जब तक हमारे तीनों भाई जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारी खुशी अधूरी है। साथ ही तब तक कोई जश्न नहीं मनाएंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। देश की जनता सब कुछ देख रही है। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मंगलवार को छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आप नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।

मतदानकर्मी बीमार हैं या नहीं, यह मेडिकल बोर्ड तय करेगा

परिवहन विशेष न्यूज

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि उसकी चुनाव में ड्यूटी रखी जाए या काटी जाए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मी प्राइवेट अस्पतालों के अलावा प्राइवेट क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों से मेडिकल फिटनेस और झूठी जांच रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। गौतमबुद्धनगर सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा।

नोएडा। लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान अगर कोई कर्मी बीमार होने के कारण ड्यूटी कटवाने के लिए आवेदन करता है तो उसपर निर्णय लेने से पहले उसे मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। मेडिकल बोर्ड स्वास्थ्य संबंधी जांच करेगा। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा कि उसकी चुनाव में ड्यूटी रखी जाए या काटी जाए।

तैयार करवाते हैं झूठी जांच रिपोर्ट

लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मी प्राइवेट अस्पतालों के अलावा प्राइवेट क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टरों से मेडिकल फिटनेस और झूठी जांच रिपोर्ट तैयार करवाते हैं। जिससे चुनाव में ड्यूटी से बचा जा सके।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील कुमार शर्मा का कहना है कि सोमवार को मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. आशा किरण चौधरी, फिजीशियन डा. हरीमोहन गर्ग को शामिल किया गया है। दोनों डॉक्टर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कार्यालय में मौजूद रहेंगे।

लोकसभा चुनाव में बीमारी का हवाला देकर अगर कोई कर्मी ड्यूटी हटवाना चाहता है तो उसे पहले मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। मेडिकल बोर्ड स्क्रीनिंग के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर कर्मी को चुनाव ड्यूटी करने या चुनावी ड्यूटी से छूट देने पर फैसला होगा।

अगर किसी की जांच की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी जांच सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में कराई जाएगी। अस्पताल में जांच के बाद यहीं के हड्डी रोग, नेत्र सर्जन, जनरल सर्जन की अनफिट होने की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। प्राइवेट अस्पतालों की जांच रिपोर्ट किसी भी आधार पर मान्य नहीं होगी।

मतदानकर्मियों के लिए तैयार हो रही 2400 किट

लोकसभा चुनाव में मतदानकर्मियों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से इमरजेंसी मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में 2200 मतदानकर्मी चुनाव ड्यूटी में लगेंगे। विभाग की ओर से 2200 के सापेक्ष 2400 किट तैयार कराई जा रही है।

चुनाव ड्यूटी में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. ललित कुमार का कहना है कि 26 अप्रैल को गौतमबुद्धनगर सीट के लिए मतदान होगा।

चुनाव में मतदानकर्मियों को बुखार, उल्टी, दस्त व अन्य किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो उसे मेडिकल किट दी जाएगी। किट में बुखार, उल्टी, दस्त, दर्द निवारक दवा के साथ ओआरएस का पैकेट रहेगा। अगर किसी मतदानकर्मी को चोट लग जाती है तो उसके लिए बैंडज भी उपलब्ध कराया जाएगा।

मतदानकर्मियों के इलाज को अस्पतालों की पहचान

मतदानकर्मियों के बीमार पड़ने की स्थिति में उनका आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज में होगा। इसके लिए सभी अस्पतालों को सूचित कर दिया गया है। बेड भी आरक्षित करने को निर्देशित किया गया है। ज्यादातर राज्यकर्मी पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अधीन कवर होंगे।

व्यवस्था बनाने को नामित किए नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। जिसमें एसीएमओ डा. ललित कुमार, डिप्टी सीएमओ डा. चंदन सोनी. डा. जैसलाल, डा पवन कुमार शामिल है। एंबुलेंसकर्मी के लिए बैलेट से मतदान की सुविधा चुनाव ड्यूटी में लगे एंबुलेंसकर्मी व अन्य स्वास्थ्यकर्मी मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होंगे।

गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने हड़पे 1.25 लाख रुपये

इंदिरापुरम। सीआईएसएफ के पास बस के इंतजार में खड़े युवक को दो शातिरों ने सरकारी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने बिहारी मार्केट ले जाकर बेसुध कर दिया। फिर जेब से नकदी, डेबिट व क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर 1.25 लाख रुपये हड़प लिए। उन्होंने इंदिरापुरम पुलिस को मुकदमा कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में रहने वाले सचिन ठाकुर 23 मार्च की दोपहर साढ़े तीन बजे मुरादाबाद जाने के लिए सीआईएसएफ के पास बस का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास बाइक सवार दो युवक पहुंचे। एक ने उनसे कहा कि उसके पास सरकारी गाड़ी है। उसमें उन्हें वह मुरादाबाद तक लिफ्ट दे देगा। उन्होंने युवक की बात पर विश्वास किया और तीनों बाइक पर बैठ गए। दोनों उन्हें नीतिखंड चौकी क्षेत्र की बिहारी मार्केट में ले गए। वहां उनके चेहरे पर धुआं मारकर बेसुध कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने जेब से 40 हजार रुपये की नकदी, डेबिट कार्ड से 30 हजार रुपये और क्रेडिट कार्ड से 55 हजार रुपये की खरीदारी की। काफी देर बाद उन्हें होश आया तो फोन पर खाते से नकदी निकालने के ओटीपी देखकर होश उड़ गए। उन्होंने दोनों बाइक सवार युवकों को इधर-उधर देखा लेकिन वे भाग गए थे। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करने के दौरान पुलिस ने उन्हें चक्कर कटाया। वह पहले विजयनगर थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने इंदिरापुरम की घटना बताकर कोतवाली में शिकायत करने भेज दिया। इंदिरापुरम एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि फुटेज से दोनों आरोपियों की पहचान करके टीम तलाश कर रही है।

दोपहिया वाहन चुराने वाले तीन गिरफ्तार, 17 वाहन बरामद

रविवार रात कोतवाली पुलिस क्षेत्र में क्रासा चौराहे के पास से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान तीन संदिग्ध लोग बाइक पर सवार होकर आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा किया तो तीनों आरोपित भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा करके तीनों को पकड़ लिया। बाइक की जांच की तो पता चला कि वह चोरी की है। पुलिस आरोपितों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।

नोएडा। कोतवाली सेक्टर-142 पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में रेकी कर दोपहिया वाहन चोरी करने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर विभिन्न स्थान से चोरी किए गए 17 वाहन बरामद किए हैं।

एडीसीपी ह्देश कठेरिया ने बताया कि रविवार रात कोतवाली पुलिस क्षेत्र में क्रासा चौराहे के पास से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान तीन संदिग्ध लोग बाइक पर सवार होकर आते दिखाई दिए। रुकने का इशारा किया तो तीनों आरोपित भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा करके तीनों को पकड़ लिया।

आरोपितों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस

बाइक की जांच की तो पता चला कि वह चोरी की है। आरोपितों की पहचान हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र की पुरानी चुंगी के नईम उर्फ रहीम, दिल्ली सोनिया विहार के इमरान और बदायूं के गांव ओरछी के जुल्फिकार के रूप में हुई है।

पूछताछ के दौरान आरोपितों की निशानदेही पर विभिन्न स्थान से 17 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पुलिस आरोपितों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। साथ ही बरामद दोपहिया वाहनों का पता लगाने में जुटी है कि वह कहां से चुराए गए हैं।

ऑटो मालिक और उसके रिश्तेदार पर चालक ने किया हमला

इंदिरापुरम। कनावनी में ऑटो चालक से हिसाब करने गए मालिक और उनके साले पर कहासुनी के बाद हमला कर दिया। इंदिरापुरम पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार लिया है। वसुंधरा निवासी ऑटो मालिक करन सिंह ने बताया कि वह अपने साले वेदप्रकाश के साथ चालक से वाहन का हिसाब करने गए थे। वहां चालक मुजामिल अली से गड़बड़ी पर विवाद हो गया। आरोप है कि उसने गाली-गलौज के बाद दो भाइयों को बुला लिया। सभी ने मिलकर दोनों पर हमला कर दिया। मारपीट में दोनों को काफी चोट आईं। लोगों के एकत्रित होने पर आरोपी घायलों को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इंदिरापुरम पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपी और उसके भाइयों को पकड़ लिया है।

कारोबारी को बंधक बनाकर लूटा, केस दर्ज

मोदीनगर। भोजपुर के गांव नाहली से रविवार रात दुग्ध प्लांट बंद कर घर लौट रहे कारोबारी को अगवा कर कमरे में बंधक बनाकर नकदी लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने विरोध करने पर कारोबारी को जमकर पीटा और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत तीन नामजद व कई अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।

दोहरा हत्याकांड: तीन पुलिसकर्मी निलंबित, व्यापारियों ने जाम लगा किया हंगामा; मौके पर पहुंचे एसपी सिटी

बुलंदशहर के देहात कोतवाली में दो लोगों की हत्या के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

देहात कोतवाली क्षेत्र में हुई नगर निवासी दो लोगों की हत्या मामले में एसएसपी ने कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर एसएसपी ने देहात कोतवाली के तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। दूसरी ओर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतकों के परिजनों ने मंगलवार सुबह बुरा बाजार चौराहे पर जाम लगाकर हंगामा किया। जिसे एसपी सिटी ने पहुंच कर लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया और जाम खुलवाया।

नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शेख सराय निवासी 50 वर्षीय राजीव कुमार गर्ग उर्फ पिंटू और उनके फूफा सुधीर चंद निवासी गांधी चौक की रविवार शाम को गला रेत व धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव सोमवार देर शाम देहात कोतवाली क्षेत्र में अडौली नहर की पटरी पर पुलिस ने बरामद किए।

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उक्त घटना के मामले में मृतकों के परिजनों द्वारा रविवार रात को ही थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी की सूचना कार्यलेख पर नियुक्त हेडकंस्टेबल कमल हसन व पीसी भूड़ चालक हेडकंस्टेबल अनुज पारासर और कांस्टेबल विवेक को दी गई थी। जिनके द्वारा न तो उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और न ही कोई विधिक कार्रवाई की गई। इससे प्रारंभिक जांच में उक्त पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आ रही है। इसी के चलते एसएसपी ने तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है।

वहीं, दूसरी ओर हत्याकांड से क्षुब्ध मृतकों के परिजनों और व्यापारियों ने मंगलवार सुबह बुरा बाजार चौराहे पर पहुंच कर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप था कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है, साथ ही परिजनों ने जल्द से जल्द वारदात का खुलासा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। व्यापारियों और परिजनों के जाम लगने से चौराहे पर करीब दो घंटे तक वहां जाम में फंसे रहे।

गौतमबुद्ध नगर में छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जा रहा मतदान का महत्व, ताकि अव्वल दर्जे से पास हों फिसड्डी बूथ

गौतमबुद्ध नगर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जिले में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं को मतदान का महत्व पढ़ाया जा रहा है। छात्र-छात्राएं अपने साथ दूसरों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करें उन्हें शपथ दिलाई जा रही है। साथ ही बुजुर्गों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर को शिक्षा का हब कहा जाता है। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 300 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान हैं। जहां देश के विभिन्न राज्यों से आकर छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग, बी-फार्मा, एमबीए, बीबीए, एमबीबीएस आदि की उच्च कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत इस बार भी पांच हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराया है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों में शिविर आयोजित कर आवेदन स्वीकृत किए गए थे। छात्र-छात्राओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में किसी तरह की परेशानी न हो, ऐसे में शिक्षण संस्थानों में मतदेय स्थल भी बनाए जाते हैं।

उसके बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं मतदान करने को लेकर उदासीन हैं। अंदाजा पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत मतदाता छात्र-छात्राओं के लिए बनाए गए बूथों पर पड़े मतदान को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है।

ऐसे बूथों की तैयार की जा रही लिस्ट

दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर ऐसे बूथों की सूची तैयार कराई गई जहां मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा। हैरत की बात यह रही कि जिले के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए बनाए गए बूथों पर मतदान का प्रतिशत बेहद कम रहा।

ऐसे बूथों को चिह्नित करने के बाद स्वीप कार्यक्रम (मतदाता जागरूकता अभियान) के तहत शिक्षण संस्थानों में गोष्ठी आयोजित कर वहां पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को मतदान करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीडीओ जनार्दन सिंह को नोडल अफसर व जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

स्वीप कार्यक्रम के तहत शिक्षण संस्थानों में गोष्ठी आयोजित कर छात्र-छात्राओं को मतदान करने का महत्व समझाया जा रहा है। छात्र-छात्राएं अपने साथ दूसरों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करें उन्हें शपथ दिलाई जा रही है।

-शैलेंद्र बहादुर सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी

इंडिया की लोकतंत्र बचाओ महारैली के बेसुरे स्वर

ललित गर्ग

इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओं रैली में भारतीय जनता पार्टी एवं पीएम मोदी की शानदार जीत की संभावना से बौखलाए नेताओं की खींच ही ज्यादा सामने आयी है। यही कारण है कि रैली में जो मुद्दा जोरशोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी।

> इस रैली में अनेक मुद्दे उठे, जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। प्रियंका गांधी ने इस रैली में सरकार के सामने पाँच माँगें रखीं। इनमें प्रमुख दो हैं जिनमें चुनाव आयोग से माँग की गई है कि विपक्षी नेताओं पर छापों की कार्रवाई रोकी जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण माँग ये है कि गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए।

दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओं महारैली में जुटे 28 दलों के नेता आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कोई प्रभावी संदेश देने में नाकाम रहे हैं। भले ही चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने में कामयाबी हासिल की हो। लेकिन यह एकजुटता भ्रष्ट नेताओं को बचाने की एक मुहिम ही बनकर सामने आयी है। इसमें स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार की भ्रष्टाचार पर गई कार्रवाई की बौखलाहट झलक रही थी। इस रैली में सभी दलों के नेताओं ने देश विकास के मुद्दों, सिद्धान्तों एवं नैतिक तकाजे की बजाय मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसी के इर्दगिर्द ही अपनी बातें रखीं। लोकतंत्र बचाओ रैली से उपजे विचारों ने किन्हीं पवित्र उद्देश्यों के बजाय सत्ता हासिल करने की लालसा को ही उजागर किया, यह निराश करने वाली रैली किसी बड़े बदलाव की वाहक बनती हुई नजर नहीं आयी।

इस रैली में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शानदार जीत की संभावना से बौखलाए नेताओं की खींच ही ज्यादा सामने आयी है। यही कारण है कि रैली में जो मुद्दा जोरशोर से उठा, वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। आम जनता के मतों से जीत हासिल करने वाला दल किस तरह से लोकतंत्र को ध्वस्त करने वाला हो सकता है। विपक्षी एकता का यह महाकुंभ मोदी को कोसने की बजाय किन्हीं ठोस मुद्दों के सहारे कोई प्रभावशाली विमर्श खड़ा करने की कोशिश करता तो वह आम जनता को आकर्षित करता और यही स्वस्थ राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक होता। लेकिन ऐसा न होना समूचे देश के विपक्षी दलों की नाकामी, उद्देश्यहीनता एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का द्योतक हैं।

इस रैली में अनेक मुद्दे उठे, जिनमें प्रमुख रहा केंद्रीय एजेंसियों का कथित दुरुपयोग और राजनीतिक भ्रष्टाचार। प्रियंका गांधी ने इस रैली में सरकार के सामने पाँच माँगें रखीं। इनमें प्रमुख दो हैं जिनमें चुनाव आयोग से माँग की गई है कि विपक्षी नेताओं पर छापों की कार्रवाई रोकी जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण माँग ये है कि गिरफ्तार हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। इस रिहाई की माँग के पीछे कांग्रेस का उद्देश्य बचे-खुचे संगठनों या पार्टियों को इंडिया गठबंधन से जोड़े रखना है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे मज़बूत खम्भे पहले ही उखड़ चुके हैं इसलिए जो कुछ बचा है उसे कांग्रेस समेटे रखना चाहती है, यही उसकी विवशता है। वैसे, इंडिया गठबंधन के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी इस रैली दिखी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। जबकि इस रैली का मकसद आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया। यहां आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस के बीच के अन्तर्विरोध को सहज ही समझा जा सकता है।

यह रैली भले ही अठाइस दलों का जमावड़ा बनी, इसे विपक्षी दलों की एकजुटता का प्रदर्शन भी कहा गया है। लेकिन जबसे इंडिया गठबंधन बना है, तब से उसमें टूट एवं बिखराव के स्वर सुनाई दे रहे हैं। विचारभेद के साथ मनभेद भी सामने आये हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया गठबंधन से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें भी आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, लेकिन संदेश स्पष्ट था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी इंडिया गठबंधन से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रामलीला मैदान की रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि मोदी विरोध एवं भाजपा को सत्ता से दूर करने के मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं और लगातार बोलते भी रहे हैं, फिर उसके लिये इस महारैली की क्या जरूरत? निश्चित ही एकजुटता के ये स्वर बेसूरे, असहज एवं बनावटी है, इंडिया गठबंधन के राजनैतिक क्षितिज पर जो वरिष्ठ राजनेता हैं उनकी आवाज व किरदार भारतीय जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन से जुडे.दलों की केन्द्र एवं प्रांतों की सरकारों के शासन-काल में तो अपराध, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता के जबड़े फैलाए, आतंकवाद, प्रांतवाद, जातिवाद की जीभ निकाले, मगरमच्छ सब कुछ निगलता रहा है। सब अपनी जातियों और ग्रुपों को मजबूत करते रहे हैं-- देश को नहीं। प्रथम पंक्ति का नेता ही नहीं है जिसे मोदी के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। भारत के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।

दो तरह के नेता होते हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो आज भी वे भारत को विकास की नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इंडिया गठबंधन की चोटी से लेकर प्रांत स्तर पर, समाज स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। यह सोच का दिवालियापन ही है कि दिखते हुए भ्रष्टाचार के बावजूद उसका विरोध नहीं करके, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिये लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन हो रहे हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन वह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मेरठ में चुनावी महासंग्राम की शुरुआत करते हुए कहा कि अगर विपक्षी नेता पाक-साफ़ हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ क्यों नहीं रहा है? कुछ तो गड़बड़ होगी ही। कुल मिलाकर बयानों का तीखापन यहाँ- वहाँ आने लगा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में धार आ गई है। यह धार दिन ब दिन और पैनी होती जाएगी।

भारत के केनवास पर शांति, प्रेम, ईमानदारी, विकास और सह-अस्तित्व के रंगों की जरूरत है, पर आज इंडिया गठबंधन इन रंगों को भरने की पात्रता खोकर नायकविहीन है। रंगमंच पर नायक अभिनय करता है, राजनीतिक मंच पर नायक के चरित्र को जीना पड़ता है, कथनी-करनी में समानता, दृढ़ मनोबल, इच्छा शक्ति और संयमशीलता के साथ। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यह एक बड़ी विडम्बना है कि यहां विपक्षी दलों में नायक कम, खलनायक अधिक है। तभी एक मोदी अठाइस दलों के नेताओं पर भारी पड़ रहा है। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। विपक्षी दलों ने जो मुद्दे उठाये, वे प्रभाव पैदा नहीं कर पाये। चुनावी बांड का ही मुद्दा ले, इसमें संदेह नहीं कि चुनावी बांड से दिए जाने वाले चंदे का जो विवरण सामने आया है, उससे अनेक गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिन कंपनियों का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने उन पर अनुचित दबाव डालकर चंदा हासिल किया, उनमें से अनेक ने विपक्षी दलों को भी अच्छा-खासा चंदा दिया है।

टेस्ला को दिख रहा है एक निराशाजनक भविष्य ? वैश्विक स्तर पर ईवी की मांग कम होने के साथ हैं कई वजहें

टेस्ला इंक . एक निराशाजनक मुकाम की ओर बढ़ रही है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की घटती मांग और बढ़ती ब्याज दरों ने वाहन निर्माता की बिक्री पर असर डाला है। एक मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलन मस्क के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने मार्च 2024 को खत्म हुई पिछली तिमाही में 449,080 इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी की। जो दिसंबर 2023 को खत्म हुई पिछली तिमाही में दर्ज की गई कंपनी की बिक्री से सात प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

परिवहन विशेष न्यूज

एक अन्य मीडिया रिपोर्ट ने भी इशाका किया है कि टेस्ला एक निराशाजनक तस्वीर देख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में टेस्ला कार खरीदने वाले संभावित ग्राहकों की संख्या घट रही है। इस गिरावट का एक कारण टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का विवादास्पद व्यक्तित्व बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला ने 2023 में आक्रामक मूल्य कटौती और छूट के कारण बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज करना जारी रखा। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता का कंसीडरेशन स्कोर इस साल फरवरी में घटकर 31 प्रतिशत हो गया, जो नवंबर 2021 में दर्ज किए गए ब्रांड के 70 प्रतिशत स्कोर की तुलना में आधे से भी कम है। रिपोर्ट में इस डेटा का श्रेय कैलिबर को दिया गया है। जो पिछले कुछ वर्षों में ब्रांड में उपभोक्ताओं की दिलचस्पी पर नजर रख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला के सीईओ ने मार्च 2024 के आखिरी हफ्तों में कंपनी की मदद नहीं की। उन्होंने कथित तौर पर एक नए निर्देश को लागू किया जो बिक्री प्रक्रिया को धीमा कर देता। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तरी अमेरिका में टेस्ला के हर ग्राहक को अब ड्राइवर असिस्टेंस फीचर की टेस्टिंग करने के लिए छोटी ड्राइव लेने की जरूरत है। जिसे कंपनी भ्रामक रूप से फुल सेल्फ ड्राइविंग के रूप में बेचती है।

ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई हैं जब टेस्ला के सीईओ ने दावा किया है कि कंपनी दो प्रमुख विकास लहरों (ग्रोथ वेव) के बीच में है। पहली लहर मॉडल 3 सेडान और मॉडल Y एसयूवी द्वारा संचालित थी। और अगले को 2025 के आखिर में उत्पादन शुरू होने वाली एक सस्ती नेक्स्ट जेनरेशन इलेक्ट्रिक कार के लॉन्च से उम्मीद है।

कई झटकों ने भी टेस्ला की इस साल की पहली तिमाही की बिक्री को प्रभावित किया। जर्मनी में बर्लिन के बाहर स्थित अपने मैन्युफेक्चरिंग प्लांट के कई बार बंद होने से कंपनी को एक बड़ा झटका लगा। कंपनी ने कैलिफोर्निया में अपने कारखाने को मॉडल 3 सेडान का एक अपडेटेड वर्जन बनाने के लिए भी अपग्रेड किया। जिसने शायद उत्पादन को धीमा कर दिया। इसके अलावा बाजार में तेजी से बढ़ते कॉम्पीटिशन से भी टेस्ला की बिक्री प्रभावित हो रही है।

चीन में, जो टेस्ला के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है, वहां वाहन निर्माता कंपनी BYD कं. के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। जो पिछले साल के आखिर में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी बन गई।

टोल टैक्स रिवीजन पर रोक लगने के बाद NHBF ने मांगा मुआवजा, 1 अप्रैल से होनी थी बढ़ोतरी

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार(1 अप्रैल) को NHAI से लोकसभा चुनाव पूरा होने तक राजमार्गों पर टोल संशोधन को स्थगित करने के लिए कहा है। इससे पहले एनएचएआई ने 1 अप्रैल से पूरे देश में राजमार्गों पर टोल टैक्स रिवाइज करने की बात कही थी। इसको लेकर एनएचबीएफ के महानिदेशक पी. सी. ग्रोवर ने एनएचएआई अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है।

नई दिल्ली। नेशनल हाईवे बिल्डर्स फेडरेशन ((NHBF) ने मंगलवार को मांग करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद टोल रिवीजन स्थगित होने के कारण राजस्व के नुकसान के लिए रियायतकर्ताओं को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एनएचबीएफ राजमार्ग डेवलपर्स संगठन का एक प्रमुख निकाय है।

चुनाव आयोग ने लगा दी रोक

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार(1 अप्रैल) को NHAI से लोकसभा चुनाव पूरा होने तक राजमार्गों पर टोल संशोधन को स्थगित करने के लिए कहा है। इससे पहले एनएचएआई ने 1 अप्रैल से पूरे देश में राजमार्गों पर टोल टैक्स रिवाइज करने की बात कही थी।

एनएचबीएफ के महानिदेशक पी. सी. ग्रोवर ने एनएचएआई अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर टोल शुल्क संशोधन दर को स्थगित करने पर आपके (एनएचएआई अध्यक्ष) द्वारा राजस्व के नुकसान के लिए हमारे सदस्यों को नकद मुआवजा प्रदान किया जाए। उन्होने आगे कि अगर कोई वैधानिक आदेश नहीं होता तो उन्हे(NHBH) ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती।

ग्रोवर ने इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा कि क्या टोल/शुल्क दर संशोधन को उस विशेष राज्य की मतदान तिथियों के आधार पर रियायतग्राही द्वारा लागू किया जा सकता है, जिसमें संबंधित राजमार्ग स्थित हैं या संशोधन के कार्यान्वयन के लिए एनएचएआई द्वारा एक आम तारीख की घोषणा की जाएगी।

NHBF का प्लान क्या था ?

टोल बढ़ोतरी का वार्षिक संशोधन, जो औसतन 5 प्रतिशत की सीमा में होने की उम्मीद थी, देश भर के अधिकांश टोल वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे हिस्सों के लिए 1 अप्रैल को लागू होना था। एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, टोल शुल्क में बदलाव उन दरों को संशोधित करने की वार्षिक कवायद का हिस्सा है, जो थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव से जुड़ी हैं।

कब शुरू होंगे आम चुनाव

18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लगभग 855 उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा हैं, जिन पर राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाता है।

Maruti Suzuki ने तोड़े बिक्री के सभी रिकॉर्ड, FY24 में सेल्स का आंकड़ा 20 लाख के पार

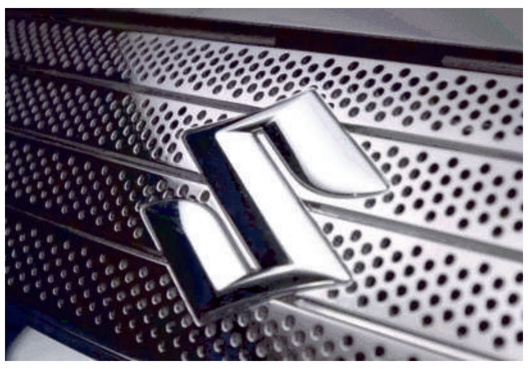

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने मार्च 2024 में कुल 187196 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया है। कंपनी ने एक वितीय वर्ष में 1793644 यूनिट के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक घरेलू बिक्री और 283067 यूनिट का अब तक का सबसे अच्छा निर्यात दर्ज किया। ऑल्टो और एस-प्रेसो वाले मिनी सेगमेंट में मारुति सुजुकी ने सालाना आधार पर 2.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने मार्च 2024 में कुल 1,87,196 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया है। कुल बिक्री में 1,56,330 यूनिट की घरेलू बिक्री, अन्य ओईएम को 4,974 यूनिट की बिक्री और कुल 25,892 यूनिट का निर्यात शामिल है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 को एक वित्त वर्ष में अब तक की सबसे अधिक कुल बिक्री के साथ समाप्त किया।

सामने आए बिक्री के आंकड़े

मारुति सुजुकी ने एक वित्तीय वर्ष में 1,793,644 यूनिट के साथ अपनी अब तक की सबसे अधिक घरेलू बिक्री और 2,83,067 यूनिट का अब तक का सबसे अच्छा निर्यात दर्ज किया। ऑल्टो और एस-प्रेसो वाले मिनी सेगमेंट में, मारुति सुजुकी ने सालाना आधार पर 2.13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 11,582 यूनिट के मुकाबले 11,829 यूनिट पोस्ट की हैं, जबकि सियाज मिडसाइज सेडान ने केवल 590 यूनिट ही दर्ज कीं।

कमर्शियल व्हीकल की घटी मांग

बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट, टूर एस और वैगनआर की कॉम्पैक्ट रेंज ने पिछले महीने 69,844 यूनिट की घरेलू बिक्री दर्ज की, जबकि बारह महीने पहले इसी अवधि के दौरान 71,832 यूनिट की बिक्री हुई थी, जिसमें सालाना आधार पर 2.76 प्रतिशत की गिरावट आई है। हाल के वर्षों में यूवी पोर्टफोलियो में अक्सर विस्तार देखा गया है और मारुति सुजुकी को इसका लाभ मिल रहा है। इसमें ब्रेजा, अर्टिगा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी और XL6 शामिल हैं। इसे मार्च 2024 में 58,436 यूनिटका योगदान देने का श्रेय दिया जा सकता है, जबकि 57.7 प्रतिशत की सकारात्मक बिक्री वृद्धि के साथ 37,054 इकाइयों का योगदान है। FY2023-24 में इंडो-जापानी निर्माता ने 6,42,296 यूनिट UV बिक्री दर्ज की और यह सेगमेंट में अग्रणी रही।

एक्सपोर्ट में आई कमी

साल-दर-साल 14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 30,119 यूनिट की तुलना में पैसेंजर कारों की कुल 25,892 यूनिट का निर्यात किया गया। ब्रांड आने वाले महीनों में नई पीढ़ी की स्विफ्ट को पेश करने की योजना बना रहा है, जबकि ऑल न्यू डिजायर भी 2024 की दूसरी छमाही में लॉन्च के लिए तैयार है। इसके बाद ग्रैंड विटारा का 7-सीटर संस्करण और ब्रांड का पहली इलेक्ट्रिक कार 2025 में आएगी।

इस साल लॉन्च हो रही हैं ये 2 नई सेडान कार, फीचर से माइलेज तक सब होगा खास

Maruti की Dzire सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में शामिल है। अपडेट के बाद निश्चित रूप से इसकी मांग और बढ़ने वाली है। Honda Amaze एक बॉक्सी डिजाइन वाली सेडान कार है जो काफी व्यावहारिक और बड़े केबिन के साथ आती है। जो कम बजट में ज्यादा जगह वाली सेडान की तलाशते हैं उनके लिए ये बेहतर विकल्प है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। समय के साथ सेडान कारों की मांग घट रही है। इसके बावजूद भी देश की दो पॉपुलर कंपनियां नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही हैं। इसमें नई Maruti Suzuki Dzire और Honda Amaze शामिल है। आइए, इनके बारे में जान लेते हैं।

Maruti Suzuki Dzire

Maruti की Dzire सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कारों में शामिल है। अपडेट के बाद निश्चित रूप से इसकी मांग और बढ़ने वाली है। फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, नया 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले में सक्षम है। एक्सटीरियर पर नया डिजाइन आने वाली नई स्विफ्ट के समान होगा।

यांत्रिक रूप से हम उम्मीद करते हैं कि ये आजमाए हुए और भरोसेमंद 1.2-लीटर 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ही आएगी, जो 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन विकल्प में 5-स्पीड मैनुअल या 5-स्पीड एएमटी शामिल है। हालांकि, उम्मीद है कि सुजुकी बिल्कुल नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन ला सकती है, जो कथित तौर पर एक हाइब्रिड यूनिट से जुड़ा है, जो अधिक परफॉरमेंस और फ्यूल एफिशियंशी के साथ आएगा।

Honda Amaze

Honda Amaze एक बॉक्सी डिजाइन वाली सेडान कार है, जो काफी व्यावहारिक और बड़े केबिन के साथ आती है। जो कम बजट में ज्यादा जगह वाली सेडान की तलाशते हैं, उनके लिए ये बेहतर विकल्प है।

अपडेटेड अमेज में होंडा से चीजों को एक पायदान ऊपर ले जाने और बजट और ग्राउंड क्लीयरेंस से समझौता किए बिना अधिक प्रीमियम और व्यावहारिक सेडान पेश करने की उम्मीद है।

प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने की जरूरत

हंसराज ठाकुर

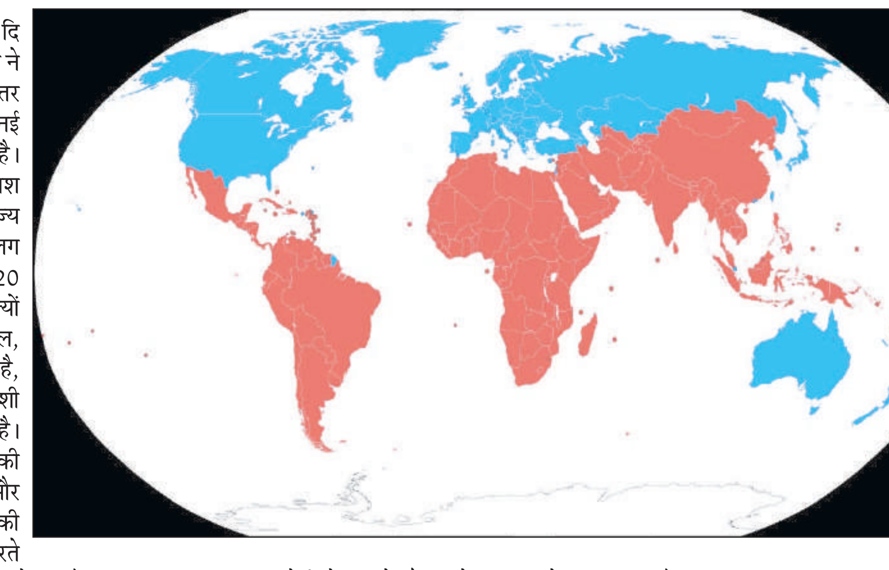

हाल ही में लंदन से प्रकाशित 'दि इकोनॉमिस्ट' नाम की एक पत्रिका ने एक बेहद शरारती लेख के जरिए उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की नई परिभाषा गढने की कोशिश की है। पत्रिका यह दावा करने की कोशिश करती है कि दक्षिण भारतीय राज्य आर्थिक दृष्टि से शेष भारत से अलग हैं। क्योंकि भारत की केवल 20 प्रतिशत आबादी पांच दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में रहती है, लेकिन इन राज्यों को कुल विदेशी निवेश का 35 प्रतिशत प्राप्त होता है। इन राज्यों ने देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकास किया है और जहां 1993 में ये राज्य देश की जीडीपी का 24 प्रतिशत उत्पन्न करते थे, वहीं अब यह बढक़र 31 प्रतिशत हो गया है। 46 प्रतिशत टेक यूनिकॉर्न दक्षिण भारत से हैं और भारत का 46 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात इन्हीं पांच दक्षिणी राज्यों से होता है। इतना ही नहीं, पत्रिका लिखती है कि 66 फीसदी आईटी सेवाओं का निर्यात भी दक्षिणी राज्यों से होता है। कुछ एजेंडाधर्मी लोगों को छोड़, सारा विश्व जनता है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत एक है। इस उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी लोग विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, वेशभूषा और खानपान के बावजूद स्वयं को भारतीय मानते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है : 'उत्तरं यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्। वर्षम्तद् भारतम्नाम भारती यत्र सन्तिः।' इसका अर्थ है : समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूमि को भारत भूमि कहा जाता है और भारत की इस पवित्र भूमि पर रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। यह सच है कि भारत में अलग-अलग क्षेत्रों पर अलग-अलग समय में अलग-अलग शासकों का शासन था, लेकिन पूरे भारत में रहने वाले सभी लोगों के बीच एक अटूट संबंध बना रहा।

देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हमारे ज्योतिर्लिंग, तीर्थ और धाम इस बात के गवाह हैं कि सभी भारतीय पूरे राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानते रहे हैं और भाषायी, क्षेत्रीय, खानपान और अन्य विविधताएं कभी भी इसमें बाधक नहीं बनीं। लेकिन अफसोस की बात है कि विदेशी शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा साहित्य रचा गया और जानबूझ कर इतिहास लेखन के माध्यम से झूठी कहानियां गढ़ी गईं, जिससे दक्षिण भारत के लोगों के मन में उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ जहर भर गया। झूठा इतिहास रचा गया कि, आर्य विदेशों से आए थे और उनके क्रूर आक्रमण से द्रविड़ लोग आहत होकर दक्षिण की ओर जाने को मजबूर हुए। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा के प्रति शत्रुता को दक्षिणी राज्यों में, तमिलनाडु में और भी अधिक तीव्रता से बढ़ावा दिया गया। कहा जाता है कि इस झूठी कहानी की शुरुआत एक जर्मन प्राच्यविद् और भाषाशास्त्री ने की थी। आज प्रचुर मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत पूरी तरह से एक मिथक, मनगढ़ंत और काल्पनिक है, और अवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। भारत, अमरीका और अन्य देशों के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में प्रकाशित शोध पत्रों के अनुसार, हड़प्पा काल के वैज्ञानिक तथ्यों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य एशिया से आर्यों का इतने बड़े पैमाने पर प्रवास कभी नहीं हुआ। इसके अलावा कई इतिहासकारों ने भी इस झूठी कहानी को उजागर करने का काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भारत में हो रहे तेजी से विकास से ईर्ष्या करने वाले पश्चिमी दुनिया के देशों द्वारा यह एजेंडा लगातार चलाया जा रहा है। दक्षिण में हुए विकास के आंकड़ों का सहारा लेकर, पत्रिका ने शरारतपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ा और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिणी राज्यों में मजबूत आधार नहीं है।

पत्रिका का यह भी तर्क है कि इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार के पास पूरे देश का जनादेश नहीं है। गौरतलब है कि जिस देश (ब्रिटेन) में इकोनॉमिस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है, वहां अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को चुनाव में पूरे देश से समान जनादेश नहीं मिला है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का जनादेश नहीं है? दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब सभी क्षेत्रों से समान रूप से बहुमत वोट प्राप्त करके सरकार बनाई गई हो। इसी तरह दक्षिण भारत के कुछ नेता भी इसी प्रकार के तर्क देकर अपनी अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि देश में कुछ भ्रष्ट और अयोग्य नेताओं के कारण कई राज्यों का विकास बाधित हुआ, जिनमें दक्षिणी राज्य भी शामिल थे। पूर्वोत्तर के कई राज्य पूर्ववर्ती केंद्र सरकार की उपेक्षा के शिकार रहे हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर जैसे कई राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक संसाधन मिलते रहे। हमें यह भी समझना होगा कि हमारे सभी राज्यों का विकास एक-दूसरे के सहयोग से ही हो सकता है। जहां तक विकास का सवाल है, देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दो दक्षिण से हैं और वे भी पांचवें और छठे स्थान पर हैं, और वह भी आईटी सेक्टर के कारण, जहां भारत के सभी हिस्सों से आने वाले लोग काम कर रहे हैं। जहां हमारे देश में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में उत्तरी राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पाद उपलब्ध कराने में दक्षिणी राज्यों के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार भारत एक परिवार की तरह है और सभी राज्य इसके सदस्य हैं।

परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इसमें अमीर-गरीब का कोई विचार नहीं है, जरूरत इस बात की है कि सब मिलकर काम करें और अपने अभिन्न परिवार यानी भारत को समृद्ध बनाएं। इसके अलावा, हम 'वसुधैव कुटुंबकम', यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, को मानने वाले हैं। राजनीतिक उद्देश्यों वाले लोगों ने अब दक्षिणी राज्यों को कर-धन के हस्तांतरण में भेदभाव का मुद्दा उठाकर उत्तर-दक्षिण विभाजन को एक और आयाम दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि दक्षिणी राज्यों को केंद्रीय करों से उनके वैध हिस्से से वंचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कर हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है। 15वें वित्त आयोग की कार्यवाही के दौरान, इन राज्यों ने केंद्र सरकार के समक्ष संदर्भ की शर्तों के बारे में अपनी शिकायत व्यक्त की, जिसके अनुसार वित्त आयोग को पिछले आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली जनसंख्या को 1971 के बजाय 2011 की जनगणना के अनुसार उपयोग करने का निर्देश दिया गया था।

उनका आरोप था कि यह दक्षिणी राज्यों के खिलाफ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या को कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन यानी जनसंख्या नियंत्रण को भी महत्व दिया। हमें ध्यान देना चाहिए कि दक्षिणी राज्यों में धीमी जनसंख्या वृद्धि वहां की शिक्षा और औद्योगिक विकास के कारण थी। लेकिन अधिकांश दक्षिणी राज्य जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसंख्या नियंत्रण द्वारा पार कर चुके हैं और प्रवासी श्रमिकों पर उनकी निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जो आपसी सहयोग के महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा, केंद्रीय करों के कुल हस्तांतरण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की हिस्सेदारी पिछले वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कमोबेश वही रही। हालांकि, कर्नाटक की हिस्सेदारी 4.71 प्रतिशत से घटकर 3.64 प्रतिशत हो गई। केरल का हिस्सा इस अवधि में में 2.5 प्रतिशत से घटकर 1.92 प्रतिशत हो गया। लेकिन केंद्रीय राजस्व में हिस्सेदारी के अलावा, इन राज्यों को महत्वपूर्ण राजस्व घाटा अनुदान भी दिया गया। राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय सद्भाव के मुद्दों पर हमें अलगाववादी बयानों से बचना चाहिए।

केंद्रीय राजस्व में हिस्सेदारी के अलावा, इन राज्यों को महत्वपूर्ण राजस्व घाटा अनुदान भी दिया गया। राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय सद्भाव के मुद्दों पर हमें अलगाववादी बयानों से बचना चाहिए

संपादक की कलम से

विपक्षी एकता के मायने

राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के समर्थक और भाजपा-विरोधी बड़े नेता मौजूद थे। एकजुटता साफ नजर आ रही थी। उनमें से अधिकतर ने देश को आगाह किया कि यदि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनी, तो देश का संविधान बदलने की शुरुआत होगी। शासन और भी एकाधिकारवादी हो जाएगा। भारत रूस बन सकता है। लोकतंत्र की आत्मा खत्म कर दी जाएगी। जिस तरह रूस पर पुतिन का राज है, उसी तरह भारत में मोदी की स्थिति होगी। यह आशंका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने जताई थी। संविधान को बदलने की बात राहुल गांधी ने की, जिन्हें किन्हीं भाजपा नेताओं ने 'ब्रीफ' किया था। यहां तक आगाह किया गया कि देश में आग लग जाएगी। इनके अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, सीताराम येचुरी, भगवंत मान आदि विपक्षी नेताओं ने रोजगार का संकट, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का एमएसपी, जांच एजेंसियों की निरंकुशता और प्रशासन आदि के साझा मुद्दे उठाकर अपने लोकसभा चुनाव अभियान को गति दी। सारांश में विपक्ष की साझा रैली कई मायनों में असर छोड़ गई। एक बार फिर 'इंडिया' बिखरने के बजाय लामबंद होता दिखाई दिया। आपसी विरोधाभास को भी उन्होंने स्वीकार किया। बेशक ममता बनर्जी और स्टालिन सरीखे मुख्यमंत्री रैली में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजकर स्पष्ट किया कि वे आज भी 'इंडिया' के घटक हैं। बहरहाल विपक्षी नेताओं ने चुनावों को 'लोकतंत्र-संविधान बचाने' की सामूहिक कोशिश चित्रित किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 1857 की प्रथम क्रांति की मूलभूमि मेरठ से चुनाव के दूसरे हिस्से का आगाज किया।

उन्होंने 'भारत-रत्न' चौधरी चरण सिंह के 'गौरव समारोह' के जरिए पश्चिमी उप्र के किसानों, जाटों और 'मसीहा' के भक्त-समर्थकों को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने 'भ्रष्टाचार' के मुद्दे पर चुनावी लड़ाई की चेतावनी भी कबूल की और देश से साझा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि जनता का जो पैसा लूटा गया है, वह उसे लौटा रहे हैं। अभी तक 17,000 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को वापस किए जा चुके हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को 'मोदी की गारंटी' करार दिया और कहा कि वह विपक्ष के रुदन और चिल्लाने से घबराने वाले नहीं हैं। इन दोनों जनसभाओं का आकलन करने के बाद चुनाव विश्लेषकों की व्याख्या है कि जितना एकतरफा आम चुनाव माना जाता रहा है, उतना नहीं है। कुछ गंभीर जन-समस्याओं पर लोगों में ध्रुवीकरण होने लगा है। 'अंडर करंट' भी माना जा रहा है। उप्र और राजस्थान सरीखे राज्यों में जिस तरह एकतरफा 'मोदी लहर' आंकी जा रही थी, अब वह स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री ने बूथ स्तर के काडर को अनुरोध किया है कि वे घर-घर जाएं और कहें कि मोदी जी ने नमस्कार भेजा है।

बेशक भाजपा के पक्ष में भ्रष्टाचार के अलावा, अयोध्या राम मंदिर निर्माण, लाभार्थी योजनाएं, महिला वोट बैंक और मोदी सरकार की विभिन्न परियोजनाएं आदि हैं। यदि समूचा विपक्ष आज से ही एक सीट, एक साझा उम्मीदवार की रणनीति को अमलीजामा पहना दे और देश भर में सघन अभियान चलाए, तब भी मोदी और भाजपा-एनडीए 'दुर्जेय' हैं। चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि तमिलनाडु, केरल सरीखे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस बार प्रधानमंत्री मोदी, राम मंदिर, सनातन आदि को लेकर एक अनूठी लहर महसूस की जा रही है, लिहाजा भाजपा इस बार इन राज्यों में 'शून्य' नहीं रहेगी। यदि विपक्षी दल आपस में भाजपा-विरोधी वोटों को कम काटें और भरपूर मतदान हो, तब भी भाजपा को परास्त करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि चुनाव घोषणा से पहले ही भाजपा के काडर ने सभी बुनियादी बंदोबस्त कर दिए थे।

राय

एक ही नारा, एक ही नाम

मेरे प्रिय परिवारजनो! मैं लगातार 11वीं बार चाल क़िले की प्राचीर से झुन्नू लाल बोल रहा हूँ। अब तक आप बीजे पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे का अभ्यास बेहद असरदार तरीके से कर चुके होंगे। हमारी नज़र साल 2047 पर है। हमने विश्व गुरू को विकसित भारत बनाने का नया झुनझुना आपके हाथों में पकड़ा दिया है। जब आपका दिल चाहे आप पहले के झुनझुनों के साथ इसे बजा सकते हैं या चाहें तो अलग से बजा कर परपीड़ा की तान पर इसका आनंद ले सकते हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान देश की संसद के चुनाव जीतने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों से आप आने वाले समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको जून तक पूरी छूट है कि आप जो चाहे लिखें। इसके बाद सरकार या विश्व गुरू की आलोचना, उसकी नीतियों, योजनाओं और कार्यों की समीक्षा और टिप्पणियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी व्यक्तिगत या सांस्थानिक कुचेष्टा को सरकार गंभीरता से लेगी। ऐसा करने वाले उद्दंडियों के दिलो-दिमाग़ को दुरुस्त करने के लिए एकाग्रता शिविरों (कंसंट्रेशन कैंप) में भेज दिया जाएगा। ख़ासकर व्यंग्य लिखने वालों को अभी से भजन-चालीसा लिखने का अभ्यास आरम्भ कर देना चाहिए। लेखन की खाज मिटाने के लिए आप चाहें तो पुराणों-कथाओं का अंग्रेज़ी अनुवाद कर सकते हैं, मुझ पर या मेरी सरकार पर लेख और किताबें छाप सकते हैं। लेकिन व्यंग्य लिखने वाले एकाग्रता शिविरों में जाने के लिए तैयार रहें। हिटलर ने नाजियों को ठिकाने लगाने के लिए ज़हरीली गैसों का इस्तेमाल किया था। पर हम इसके लिए नाले की उस गैस का प्रयोग करेंगे, जिससे मैंने आपको चाय बनाना और पकौड़े तलना सिखाया है।

हो सकता है आप में से कुछ कथित बुद्धिजीवियों ने जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 'एनिमल फॉर्म' और '1984' पढ़े हों। 'एनिमल फॉर्म' की तजऱ् पर हम डिमोक्रेसी (लोकतंत्र) को बीस्टोक्रेसी (पशुतंत्र) में बदलने जा रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल चूँकि भारत के पश्चिम बंगाल के मोतीहारी में पैदा हुए थे, उन्होंने आर्यावर्त के भविष्य को काफी पहले भाँप लिया था। लेकिन वह समय का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे। नहीं तो अपने जगतविख्यात उपन्यास का नाम 1984 की बजाय 2024 रखते। जल्द ही उत्तरी कोरिया और रशिया को हम पशुतंत्र होने में मीलों पीछे छोड़ देंगे और विश्व के सबसे बड़े पशुतंत्र होंगे। लेकिन आप चिंता न करें, आपको ताउम्र पाँच किलो फ्री राशन मिलता रहेगा। जिस तरह कुत्ता सूखी हड्डी चबाते हुए अपने ही ख़ून का मज़ा लेता है, उसी तरह आप फ्री राशन का आनंद उठा सकते हैं। अन्यथा जीने के लिए सरकार आपको फ्री हवा मुहैया करवा रही है। आपको सरकार का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अभी तक उसने इस पर जीएसटी या वैट नहीं लगाया है। पर मेरे व्यापारिक मित्रों के बैंक ऋणों के हितों की रखवाली के लिए आपको आने वाले सालों में इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर वर्तमान में सरकार के विरुद्ध बनाए जा रहे वीडियोज़ पर जून में पूरी पाबंदी लागू कर दी जाएगी। इन सभी यूट्यूबर्स को अपनी रोज़ी-रोटी के लिए अभी से दूसरे प्रबंध कर लेने चाहिए।

अन्यथा एकाग्रता शिविरों में मिलने वाले घटिया आधे पेट भोजन की तैयारी कर लेनी चाहिए। अभी तो फैक्ट चैक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से स्टे है। लेकिन चुनाव आयुक्तों की तरह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की

प्राकृतिक खेती को पुनर्जीवित करने की जरूरत

हंसराज ठाकुर

प्राकृतिक खेती को मिशन बनाकर किसानों की बिगड़ती आर्थिकी को संबल प्रदान करना होगा, अन्यथा किसान कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएंगे व आत्महत्याएं करेंगे'

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है। कई किसान पृष्ठभूमि से जुड़ी विभूतियां देश के शीर्ष राजनीतिक पद तक पहुंचीं, मगर उस समय देश की आर्थिकी बहुत कमजोर थी। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा उत्पादन संभव नहीं था। आज हमारा देश चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है। विश्व भर के हर कार्य क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं अपनी चमक बिखेर रही हैं। आज देश के 58 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं। 10.07 करोड़ परिवार यानी देश के 48 फीसदी परिवार कृषि करते हैं। विश्व के 70 प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं। कम समय में ज्यादा पैसा कमाना भी सामाजिक परिवेश व सामाजिक मनोदशा के परिवर्तन का एक कारक है। कृषि के क्षेत्र में ज्यादा पैदावार की चाह हर किसान रखता है, जिसके कुछ कारण भी हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयां व कृषि यंत्र महंगे होते जा रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में खुद कार्य करने वाले किसान नाममात्र के ही रह गए हैं, बाकी सब कृषि यंत्रों, खेतों में कार्य करने वाले श्रमिकों व कृषि में प्रयुक्त होने वाले रसायनों पर निर्भर हैं। सब कुछ दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है और अनाज के दाम जस के तस बने हुए हैं। वर्ष भर मेहनत करने वाले किसान फसल बेचकर कई बार उत्पादन खर्च भी पूरा नहीं कर पाते और आमदनी बढ़ाने के लिए वे फसल के ज्यादा उत्पादन की चाह में प्राकृतिक खेती से दूर होते जा रहे हैं। कुछ प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं। पहले मनुष्य की औसत आयु 80-90 वर्ष होती थी, मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 60 से 70 वर्ष भी बमुश्किल है।

वजह थी प्राकृतिक खेती और रसायनमुक्त अनाज। आज के रसायनयुक्त अनाजों से बहुत सी जटिल बीमारियों ने इनसान को जकड़ रखा है। कहते हैं कि पृथ्वी गोल है और इनसान तेजी से ज्यादा धन कमाने की चाह में आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। किसान बेचारा कहीं पीछे भी रह जाता होगा, क्योंकि बिचौलिए कमाने की चाह में हमेशा आगे निकल जाते हैं। आखिर में इनसान वहीं पहुंच जाएगा जहां से यात्रा शुरू की थी, यानी अब इनसान को प्राकृतिक खेती के महत्त्व का एहसास होने लगा है। हिमाचल प्रदेश सरकार की 'प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना' एक अच्छी शुरुआत है जिसके तहत प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2934 पंचायतों के 72193 परिवारों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना हेतु 25 लाख रुपए के बजट का प्रावधान है जो कि नाकाफी है। पशुपालन हेतु भी किसानों को शुरुआती दौर में आर्थिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ मजबूरीवस व कुछ स्वार्थ के चलते पशुधन से दूर होते जा रहे हैं और बेचारे पशु इनसान के इस अमानवीय स्वभाव के चलते आवारा बनने को विवश हैं। पशुओं के आवारापन की दिशा में भी कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। गोबर जैसे प्राकृतिक जैविक पदार्थों की बहुमूल्यता को बनाए रखकर भी लोग पशुओं से जुड़े रहेंगे। गांव में प्राकृतिक खेती में काम आने वाले अदानों की आपूर्ति हेतु संसाधन भंडार के लिए 10000 रुपए की सहायता शीघ्रता से किसान समूह बनाकर उपलब्ध करवाई जाए। गौशाला के फर्श पक्का कर गौमूत्र इक_ा करने के लिए गड्ढा बनाने हेतु भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है, वह भी शीघ्रता से किसानों को मिले व भारतीय नस्ल की गाय की खरीद पर 50 फीसदी और अधिकतम 25000 रुपए के उपदान को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए।

इसके अतिरिक्त परिवहन हेतु 5000 रुपए की राशि का भी विशेष प्रावधान है। छोटे किसानों के लिए यह योजना कारगर साबित होगी, यानी सही ढंग से विभाग द्वारा इसे अमलीजामा पहनाए जाने की जरूरत है। अभी तक आंकड़ों के अनुसार 165221 किसान या बागवान परिवारों ने इस खेती को आंशिक या पूर्ण रूप से अपना लिया है। वह भी एक दौर था कि चाहे घड़ी इक्का-दुक्का इनसान के पास ही होती थी, समय सभी के पास होता था। मगर आज घड़ी सभी के पास होती है और समय किसी के पास नहीं है। उस दौर में बैलों से हल जोतना व फसलों की बुआई होती थी। गोबर की जैविक खाद खेतों में इस्तेमाल होती थी। गांवों के सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हुए, कितने अच्छे लगते थे। आज हर इनसान क्यों एकाकी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। ओढने के वस्त्र धोने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान के इस महंगाई के दौर में अधिकतर किसान उत्पादन का खर्च भी पूरा नहीं कर पाते, परिवार का पोषण तो दूर की बात रही। अधिकतर छोटे किसानों ने खेती करना भी छोड़ दिया है। आज अधिकतर जमीनें, जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से दूषित हो चुकी हैं। मित्र मृदा परजीवी जमीन में नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ कुछ मेहनतकश किसान प्राकृतिक खेती को अभी भी अपनाए हुए है। प्राकृतिक खेती स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ-साथ, कम उत्पादन खर्च में किसानों को अच्छा मुनाफा देती है। खेतों को मिलने वाली गोबर की जैविक खाद के परिणाम बेशक देरी से आएंगे, लेकिन साथ में स्वास्थ्य व खुशहाली भी लाएंगे। सरकारें भी धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती के प्रति कदम उठाती दिख रही हैं, मगर किसानों को इस दिशा में स्वयं पहल करनी होगी, क्योंकि सरकारें भी रासायनिक उत्पाद वाली फैक्टरियां बंद नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वह भी सरकार की आमदनी का जरिया बन चुका है।

यह तो वही बात है कि सरकार शराब व सिगरेट से समाज को होने वाले नुकसान की चेतावनी तो देती है, मगर साथ में फैक्टरी खोलने की इजाजत भी देती है। अब अपनी दशा व दिशा का निर्धारण इनसान को स्वयं ही करना होगा। बीच में बिचौलियों की भरमार तो दीमक की तरह रहेगी ही। किसान हित में कोई कारगर नीति बनानी होगी, जैसे 70 के दशक में हरित क्रांति, तत्पश्चात श्वेत क्रांति, किसानों को अच्छी नस्ल के दुधारू पशु उपलब्ध करवाना और भारतीय सहकारिता आंदोलन की नींव पड़ी, ठीक इसी तरह प्राकृतिक खेती को भी राष्ट्रव्यापी मिशन बनाकर किसानों की बिगड़ती आर्थिकी को संबल प्रदान करना होगा, अन्यथा किसान फसलों के लिए बैंकों से लिए गए कर्ज का भुगतान भी नहीं कर पाएंगे और आत्महत्या जैसे कृत्य करने को विवश हो जाएंगे, जो निश्चित रूप से देश के लिए बड़े संकट के समान होगा।

दिल्ली में राष्ट्रपति शासन!

क्या अद्र्धराज्य दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यह स्थिति 2014 में भी आई थी। तब आम आदमी पार्टी (आप) की अल्पमत सरकार थी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर आश्रित थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ही थे। वह जनलोकपाल बिल पेश करने की जिद पर थे, लेकिन उसे रोका जा रहा था। नतीजतन 49 दिन की केजरीवाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चस्पां कर दिया गया। अब 2024 में स्थितियां और राजनीतिक समीकरण बिल्कुल भिन्न हैं। दिल्ली विधानसभा में 'आप' और केजरीवाल के पक्ष में 62 विधायकों का प्रचंड बहुमत है। कुल विधायक 70 होते हैं। ऐतिहासिक जनादेश वाली, विश्वास मत प्राप्त, सरकार कार्यरत है। बेशक मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में बीते 10 दिन से हैं, लेकिन उन्होंने और 'आप' प्रवक्ताओं ने बार-बार दोहराया है कि मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाएंगे। बेशक संविधान और कानून इस संदर्भ में खामोश हैं कि भ्रष्टाचार का आरोपित और हिरासत में कैद एक मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे से ही सरकार चला सकता है अथवा नहीं। संविधान कई मामलों में खामोश है। शायद हमारे संविधान के रचनाकारों ने ऐसी स्थितियों की कल्पना ही नहीं की होगी! लेकिन इस तरह सरकार चलाने में कई व्यावहारिक और संवैधानिक बाधाएं तो आती हैं। संवैधानिक पद पर बैठे राजनेता की नैतिकता का भी कोई तकाजा है। 'आप' नेताओं की जो जिद है, वह असमर्थनीय और प्रतिकूल है। हिरासती मुख्यमंत्री किसी विचाराधीन सरकारी आदेश को अपनी पत्नी और वकील से भी साझा नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जो आदेश, उनके मंत्रियों ने, सार्वजनिक तौर पर पढ़े हैं, उन्हीं पर सत्ता के गलियारों में चर्चाएं जारी हैं कि क्या वे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ही जारी किए थे? क्या मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं? हिरासत में मुख्यमंत्री कोई बैठक तक नहीं कर सकते या आदेश की किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।

एक साथ तीन से अधिक मुलाकाती हिरासती मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते। कैबिनेट की बैठक बुलाने का आदेश नहीं दे सकते। यदि उपराज्यपाल या मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के विचारार्थ कोई फाइल भेजते हैं, तो

उसे केजरीवाल तक कौन पहुंचाएगा? गोपनीयता भंग होने के आसार पूरे हैं। लिहाजा इस संदर्भ में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का हालिया बयान बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक है। संभव है कि भारत सरकार के स्तर पर यह विचाराधीन है कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की स्थितियां बन चुकी हैं? क्या दिल्ली सरकार में संवैधानिक मशीनरी अस्थिर हो गई है? अनुच्छेद 239-बी पर भी बहस शुरू हो चुकी है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली सरकार से संबंधित अनुच्छेद को बर्खास्त कर सकती हैं? फिलहाल स्थितियां मुख्यमंत्री केजरीवाल के पक्ष में हैं कि यदि वह अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो उपराज्यपाल वैकल्पिक मुख्यमंत्री के लिए उनकी पसंद जानने की कोशिश कर सकते हैं। यदि सरकार बर्खास्त कर दी गई, तो 'आप' और सरकार के भीतर मुख्यमंत्री बनने की होड़ मच सकती है। 'आप' के नेता कोई संत नहीं हैं। फिलहाल मौजूदा सरकार के लिए फरवरी, 2025 तक का जनादेश है। बहुमत की सरकार को बर्खास्त करना भाजपा के राजनीतिक पक्ष में भी नहीं होगा। ईडी, आयकर और सीबीआई को लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार शक्ति-प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस से आयकर विभाग ने कुल 3567 करोड़ रुपए का कर और जुर्माना जमा कराने का नया नोटिस भेजा है। ये दंड 1994-95, 2017-18 से 2020-21 के सालाना आयकर से जुड़ा है। यह कोई सामान्य राशि नहीं है। कांग्रेस इसे 'टैक्स टेररिज्म' के तौर पर पेश कर राजनीति करना चाहती है। बहरहाल केजरीवाल सरकार पर ईडी का फंदा कसता जा रहा है। एजेंसी ने बीते कल एक और मंत्री कैलाश गहलोत से 5 घंटे की लंबी पूछताछ की। वह भी शराब नीति का मसविदा बनाने वाले मंत्री-समूह में शामिल थे। बहरहाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन चस्पां करना लोकसभा चुनाव के दौरान तो मुश्किल है। हालांकि शीर्ष स्तर पर चुनाव आयोग दखल नहीं दे सकता।

पेनल्टी से बचना हैं तो याद रखें अप्रैल की ये तारीखें, निपटा लें टैक्स से जुड़े सभी पेंडिंग काम

परिवहन विशेष न्यूज

1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाता है। इस दौरान नए वित्त वर्ष के लिए टैक्स संबंधित काम तो शुरू होते ही हैं साथ में पिछले फाइनेंशियल ईयर से जुड़े पेंडिंग कामों को भी निपटाया जाता है। अगर आपका भी पिछले वित्त वर्ष से जुड़ा कोई पेंडिंग काम है तो आपको अप्रैल की ड्यू के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उसके बाद पेनल्टी चुकाना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत हो गई है। यह तारीख काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव हुआ है, तो वह इसी दिन से लागू होता है। आइए जानते हैं कि अप्रैल में इनकम टैक्स के लिहाज से कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं।

इन तारीखों का ध्यान रखें टैक्सपेयर्स

7 अप्रैल: यह पिछले महीने यानी मार्च 2024 के लिए सरकार के किसी ऑफिस की ओर से कलेक्टेड या डिडक्टेड टैक्स को डिपॉजिट करने की देय तारीख (Due Date) है। हालांकि, कलेक्टेड या डिडक्टेड रकम का भुगतान सरकार के अकाउंट में उसी दिन हो जाएगा, जब आयकर चालान पेश किए बिना टैक्स का भुगतान किया जाता है।

14 अप्रैल: यह फरवरी महीने में सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की अंतिम तारीख है।

15 अप्रैल: यह मार्च 2024 को खत्म तिमाही के लिए फॉर्म नंबर 15CC में फॉरेन रेमिटेंसेज के बारे में क्वॉर्टरली स्टेटमेंट जारी करने की आखिरी तारीख है। इसे रजिस्टर्ड डीलर्स की ओर से पेश किया जाता है।

30 अप्रैल: यह काफी अहम तारीख है। इस दिन कई चीजों की ड्यू डेट है।

- यह सरकारी ऑफिस से फॉर्म 24G पेश करने की आखिरी तारीख है, जहां मार्च 2024 के लिए TDS/TCS का भुगतान चालान पेश किए बिना किया गया है।

- यह मार्च 2024 में सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194M के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-कम-स्टेटमेंट (Challan-Cum-Statement) पेश करने डेडलाइन है।

- यह मार्च के लिए उस टैक्स को जमा करने की आखिरी तारीख है, जिसे सरकारी दफ्तर के अलावा किसी अन्य असेसी ने काटा है।

- यह 1 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान प्राप्त फॉर्म नंबर 60 की डिटेल वाले फॉर्म नंबर 61 में डिक्लेरेशन की ई-फाइलिंग की आखिरी तारीख है।

- जनवरी-मार्च 2024 तिमाही के लिए फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच अपलोड करने की नियत तारीख

DGCA ने विस्तारा से मांगी रोजाना की रिपोर्ट, मंगलवार को भी विस्तारा एयरलाइंस की 50 के करीब उड़ानें हुई रद्द

परिवहन विशेष न्यूज

एविएशन मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले दिन भी 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और तकरीबन 150 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई हैं। इस संकट के पीछे एयर इंडिया और विस्तारा के विलय प्रक्रिया को बताया जा रहा है। विस्तारा में काम कर रहे पायलटों व क्रू मेंबरों का कहना है कि विलय के बाद उनके लिए जो वेतन-भत्ते प्रस्तावित है वह पर्याप्त नहीं है।

नई दिल्ली। एक साथ दर्जनों पायलटों के छुट्टी पर जाने की वजह से विस्तारा एयरलाइंस को मंगलवार को भी तकरीबन 70 घरेलू उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। कंपनी की तरफ से स्थिति को संभालने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं लेकिन हालात अस्थिर हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की एजेंसी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कंपनी से रोजाना की रिपोर्ट मांगी हैं जिसमें रोजाना रद्द होने वाली उड़ानों या उड़ान सेवा में विलंब होने को लेकर जानकारी देनी है।

नागरिक उड्डयन मंत्राल के स्तर पर भी पूरी निगरानी हो रही है। हालांकि मंत्रालय के स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम से अपने आपको अलग करने की भी कोशिश की है। विस्तारा में यह समस्या पिछले कुछ दिनों से चल रही है जो अब ज्यादा गहरा गया है।विस्तारा की तरफ से सोमवार (01 अप्रैल) को बताया गया था कि पायलटों और क्रू की उपलब्धता नहीं होने की वजह से उसने कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। कंपनी की तरह से पारदर्शी तरीके से यह सूचना नहीं दी गई है कि उसकी कितनी उड़ानें रद्द हुई हैं और कितनी उड़ानों में विलंब हुआ है।

एविएशन मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पहले दिन भी 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं और तकरीबन 150 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई हैं।टाटा समूह की इस उड्डयन कंपनी में आए इस संकट के पीछे एयर इंडिया और विस्तारा के विलय प्रक्रिया को बताया जा रहा है। विस्तारा में काम कर रहे पायलटों व क्रू मेंबरों का कहना है कि विलय के बाद उनके लिए जो वेतन-भत्ते प्रस्तावित है वह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में ये कर्मचारी अचानक ही बड़ी संख्या में छुट्टी पर चले गये जिसकी वजह से सैकड़ों उड़ानों पर असर पड़ा है।

कंपनी के सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि अभी सामान्य उड़ानों की संख्या घटाई जा रही है और रद्द उड़ानों के यात्रियों को एक साथ ले जाने के लिए ज्यादा क्षमता वाले जहाजों को सेवा में लगाया जा रहा है।

डीजीसीए ने कंपनी को कहा है कि वह रोजाना अपनी फ्लाइटों का ब्यौरा उसे दे। इसमें रद्द उड़ानों के साथ ही उन उड़ानों की जानकारी भी देनी है जिनमें विलंब हुए हैं। इसके साथ ही इससे प्रभावित यात्रियों को क्या सेवा दी गई है, इसकी जानकारी भी देने को कहा गया है।

जबकि विस्तारा एयरलाइन की मौजूदा समस्या पर चिंता जताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश डाला है। इसमें कहा गया है कि, नागरिक उड्डनय मंत्रालय विस्तार की उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। हालांकि उड़ानों का संचालन कंपनियां स्वयं ही करते हैं। एयरलाइनों को इस बारे में डीजीसीए के नियमों का पालन करना होगा कि रद्द होने की स्थिति में ग्राहकों की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है या नहीं।

इनसाइड

भारत की आर्थिक तरक्की का एक और सबूत, सरकार ने हासिल किया टैक्स कलेक्शन का टारगेट

17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा रहा। अप्रैल 2023 में जहां अब तक का सर्वाधिक संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था। वहीं मार्च 2024 में 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा। यह जीएसटी प्रणाली की अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। आइए जानते हैं पूरी खबर।

नईदिल्ली। सरकार ने मजबूत आर्थिक गतिविधि और बेहतर अनुपालन के दम पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 34.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स कलेक्शन टारगेट को लगभग हासिल कर लिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य बढ़ाकर 19.45 लाख करोड़ रुपये कर दिया था।

वहीं, इनडायरेक्ट टैक्स (जीएसटी + सीमा शुल्क + उत्पाद शुल्क) का लक्ष्य घटाकर 14.84 लाख करोड़ रुपये किया था। सरकार ने एक फरवरी को पेश बजट में संशोधित अनुमान के तहत यह लक्ष्य तय किए थे।

17 मार्च तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर मिलाकर) 18.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा रहा। अप्रैल, 2023 में जहां अब तक का सर्वाधिक संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था। वहीं मार्च, 2024 में 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा।

पहली तिमाही में रियल एस्टेट में संस्थागत निवेश में आई 40 प्रतिशत की कमी

परिवहन विशेष न्यूज

रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोलियर्स इंडिया के अनुसार जनवरी-मार्च 2024 के दौरान इस क्षेत्र में संस्थागत निवेश 99 .51 करोड़ डालर रहा है। यह 40 प्रतिशत की कमी के साथ सामने आया है। कार्यालय श्रेणी में संस्थागत निवेश 38 प्रतिशत गिरकर 56 .3 करोड़ डालर रहा है जो पिछले वर्ष समान तिमाही में 90 .76 करोड़ डालर था। आवासीय श्रेणी में निवेश 72 प्रतिशत गिरकर 10 .26 करोड़ डालर रहा है

नई दिल्ली। कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश में 40 प्रतिशत की कमी रही है। रियल एस्टेट कंसल्टेंट कोलियर्स इंडिया के अनुसार, जनवरी-मार्च 2024 के दौरान इस क्षेत्र में संस्थागत निवेश 99.51 करोड़ डालर रहा है।

कोलियर्स के अनुसार, कार्यालय, आवासीय और वेयरहाउसिंग श्रेणी में कम निवेश मिला है। जनवरी-मार्च 2023 के दौरान रियल स्टेट में संस्थागत निवेश 165.83 करोड़ डालर रहा था।

संस्थागत निवेश में आई कमी

डाटा के अनुसार, पहली तिमाही के कुल संस्थागत निवेश में विदेशी निवेशकों की 55 प्रतिशत और घरेलू निवेशकों की 45 प्रतिशत हिस्सेदारी रही है। कार्यालय श्रेणी में संस्थागत निवेश 38 प्रतिशत गिरकर 56.3 करोड़ डालर रहा है, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में 90.76 करोड़ डालर था।

आवासीय श्रेणी में निवेश 72 प्रतिशत गिरकर 10.26 करोड़ डालर रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 36.11 करोड़ डालर था। औद्योगिक एवं वेयरहाउसिंग श्रेणी में संस्थागत निवेश 18 प्रतिशत घटकर 17.77 करोड़ डालर रहा है, जो 2023 की समान अवधि में 21.63 करोड़ डालर था।

वैकल्पिक एसेट्स जैसे डाटा सेंटर, लाइफ साइंसेज, वरिष्ठ हाउ¨सग, हालिडे होम्स, स्टूडेंट हाउ¨सग और स्कूल में संस्थागत निवेश सिर्फ 2.1 करोड़ डालर रहा है।

संस्थागत निवेश में शहरों की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी

जनवरी-मार्च 2023 के 15.82 करोड़ डालर के मुकाबले इसमें 87 प्रतिशत की गिरावट रही है। मिश्रित इस्तेमाल वाली परियोजनाओं में पहली तिमाही में 13.08 करोड़ डालर का निवेश हुआ है जो पिछले वर्ष समान अवधि में सिर्फ 1.51 करोड़ डालर था।

शहरों की बात करें तो कुल संस्थागत निवेश में 26-26 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ हैदराबाद और पुणे शीर्ष पर रहे हैं। 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बेंगलुरु तीसरे स्थान पर रहा है।

ऑल टाइम हाई लेवल पहुंच कर नीचे गिरा सोना, चांदी की कीमत में आया उछाल

परिवहन विशेष न्यूज

मंगलवार को सोने की कीमतें 50 रुपये गिरकर 68370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। वहीं चांदी की कीमतें 430 रुपये चढ़कर 79000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। विदेशी बाजारों में COMEX पर सोना हाजिर 2255 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था जो पिछले बंद से 2 अमेरिकी डॉलर कम है। आइये कीमतों के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोर रुझान के बाद स्थानीय बाजार में मंगलवार को सोने की कीमतें 50 रुपये गिरकर 68,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। पिछले सत्र में सोना 68,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

हालांकि, चांदी की कीमतें 430 रुपये चढ़कर 79,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। जबकि पिछले सत्र में यह 78,570 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था।

विदेशी बाजारों में सोने की कीमत

विदेशी बाजारों में COMEX पर सोना हाजिर 2,255 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से 2 अमेरिकी डॉलर कम है। पिछले सत्र में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, मंगलवार को सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई।

आपको बता दें कि व्यापारियों ने ठोस अमेरिकी विनिर्माण डेटा के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को कम करने मंगलवार को सोने की कीमतें 50 रुपये गिरकर 68,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गईं।के फैसले पर संदेह करना शुरू कर दिया।

उच्चतम स्तर पर पहुंचा अमेरिकी डॉलर सूचकांक

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि इस बीच, अमेरिकी डॉलर सूचकांक पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिससे कीमती धातु की कीमतों पर भी असर पड़ा। हालांकि, चांदी की कीमतें 25.55 डॉलर प्रति औंस पर ऊंची थीं। इसका पिछला बंद भाव 25.13 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस था।

गांधी ने कहा कि आगे बढ़ते हुए, व्यापारियों का अनुमान है कि सराफा की कीमतें सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ ऊपरी सीमा में मजबूत होंगी और COMEX स्पॉट सोना 2,270 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार करने के बाद तेजी का रुख फिर से शुरू हो जाएगा।

IREDA के शेयरों में लगा अपर सर्किट, निवेशकों की चांदी; इस खबर का हुआ असर

परिवहन विशेष न्यूज

IREDA के शेयरों में 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में काफी शानदार प्रदर्शन किया। इससे निवेशकों को हौसला बढ़ा और उन्होंने कंपनी में जमकर पैसे लगाए। यह पिछले साल नवंबर में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। इश्यू प्राइस 32 रुपये था। यह फिलहाल 368 फीसदी की जबरदस्त उछाल के साथ 149 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA) के शेयरों में मंगलवार यानी 2 अप्रैल को 5 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। दरअसल, कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में काफी शानदार प्रदर्शन किया। इससे निवेशकों को हौसला बढ़ा और उन्होंने कंपनी में जमकर पैसे लगाए।

सरकारी कंपनी IREDA ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में उसकी लोन ग्रोथ शानदार रही। इस दौरान उसने 37,354 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया, जो अब तक सबसे अधिक है। वहीं, लोन लोन डिस्बर्समेंट 25,089 करोड़ रुपये हो गया है। IREDA की टोटल लोन बुक 59,650 करोड़ रुपये की हो गई है। इसने 26.71 प्रतिशत की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज की है।

शेयरों का क्या रहा हाल?

IREDA का शेयर आज 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 149.75 रुपये बंद हुआ। यह पिछले साल नवंबर में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। इश्यू प्राइस 32 रुपये था। यह फिलहाल 368 फीसदी की जबरदस्त उछाल के साथ 149 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। इसका ऑल टाइम हाई लेवल करीब 215 रुपये है, जिस इसने 6 फरवरी 2024 को टच किया था। हालांकि, तब से स्टॉक में 30 फीसदी की गिरावट आ चुकी है।

अब चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद निवेशकों का शेयर में भरोसा फिर से बहाल हुआ है। इससे कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी दिखी है। अब देखने वाली बात यह रहती है कि आगे इसका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है।

IREDA नए और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जरिए बिजली पैदा करने वाली प्रोजेक्ट्स को आर्थिक मदद उपलब्ध कराती है। दिसंबर 2023 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, IREDA में कम से कम 15 म्यूचुअल फंडों की 2.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वहीं, सरकार की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

कंप्यूटर विजन, एक भविष्य की तकनीक जो ऑटोमोबाइल उद्योग को परिवर्तित कर सकती है

VIRENDER SINGH
B Tech, PGDM
Director Viralka Engineers Pvt Ltd (Birla e-bike),
***President** Himachal International Federation of Electric Vehicle Association*

कंप्यूटर विजन का उपयोग करके, ऑटोमोबाइल को अपने आसपास के वातावरण को समझने की क्षमता होती है। यह सिस्टम कार को यातायात नियमों का पालन करने में मदद करता है, समीपवर्ती वाहनों का पता लगाने में सहायक होता है और अवांछित स्थिति से बचाव के लिए संकेत देता है। यह ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने में मदद कर सकता है।

इसके अलावा, कंप्यूटर विजन ऑटोमोबाइलों में ओटोनोमस ड्राइविंग के सिस्टमों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके माध्यम से, वाहन स्वचालित रूप से अपने आसपास के वातावरण को जांच सकते हैं और संभावित खतरों को पहचान सकते हैं। इससे यात्रियों को सुरक्षित यात्रा की गारंटी मिलती है।

समान रूप से, कंप्यूटर विजन सेंसर्स को ऑटोमोबाइल में स्थापित किया जा सकता है जो ड्राइवर की स्थिति को माप सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं यदि वे ध्यान नहीं दे रहे हैं या असंवेदनशील हो रहे हैं। इससे ड्राइवर के स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है और अवांछित घटनाओं से बचाव किया जा सकता है।

इस तरह, कंप्यूटर विजन ऑटोमोबाइल उद्योग को बेहतर सुरक्षा, सुगमता और अधिक उन्नत ड्राइविंग अनुभव प्रदान कर सकता है। यह न केवल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि वाहनों के संचालन को भी सुगम और प्रभावी बनाता है। कंप्यूटर विजन ऑटोमोबाइल उद्योग में हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो वाहन डिज़ाइन, विनिर्माण, परिचालन, और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को बदल रही है। इस विस्तृत व्याख्या में, हम कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी के पेशेवरता, लाभ, चुनौतियाँ, और भविष्य के आधारों पर ऑटोमोबाइलों में कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी के परिणामों की जाँच करेंगे।

1. कंप्यूटर विजन ऑटोमोबाइल में लागू होने का परिचय

- कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी का परिभाषण और अवलोकन।
- कंप्यूटर विजन का ऑटोमोबाइल उद्योग में विकास।
- वाहन सुरक्षा, दक्षता, और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में कंप्यूटर विजन की महत्वपूर्णता।

2. कंप्यूटर विजन के अनुप्रयोग

- स्वचालित ड्राइविंग सिस्टमः ज्ञान, स्थानांतरण, और निर्णय-निर्माण।
- ड्राइवर सहायता सिस्टमः लेन से विचलन चेतावनी, अनुकूलित क्रूज़ कंट्रोल, टक्कर से बचाव।
- वस्तु का पहचान और मान्यताः पैदल यात्री, वाहन, यातायात संकेत, अवरोध।
- यातायात प्रबंधन और अनुकूलीकरणः वास्तविक समय में यातायात का मॉनिटरिंग, बंदरगाह की पूर्वानुमानित दिशा।
- आंतरिक मॉनिटरिंग सिस्टमः ड्राइवर मॉनिटरिंग, अधिग्रहण का पता लगाना, हस्तक्षेप नियंत्रण। - विनिर्माण और गुणवत्ता नियंत्रणः दोष पता लगाना, संश्लेषण लाइन स्वचालन, रोबोटिक विज़न।

3. कंप्यूटर विजन सिस्टमों का काम करने का सिद्धांत

- सेंसर और डेटा अधिग्रहणः कैमरे, लीडार, रेडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। - छवि प्रसंस्करण और विश्लेषणः सुविधा निकालना, वस्तु विभाजन, पैटर्न मान्यता। - वास्तविक समय में प्रसंस्करण और निर्णय-निर्माणः त्वरित प्रतिक्रिया के लिए निम्न विलम्ब एल्गोरिदम।
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदमः कनवोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स (CNNs), गहरी सीखने वाले मॉडल। - सेंसर फ्यूजन और डेटा एकीकरणः मल्टीपल सेंसरों से जानकारी का एकीकरण करने के लिए।

4. कंप्यूटर विजन के लाभ

- बढ़ी सुरक्षाः घातक दुर्घटनाओं का कम होना, बेहतर ड्राइवर जागरूकता, आपात समय में प्रवेश। - अधिक दक्षताः यातायात प्रवाह का अनुकूलन, बंदरगाह कमी, ईंधन बचत । - उपयोगकर्ता अनुभव में सुधारः ड्राइवर सहायकता सुविधाओं का सहज एवं अभिनव इंटीग्रेशन। - लागत की बचतः कम बीमा वित्तीय प्रीमियम, कम रखरखाव लागत, विनिर्माण प्रक्रियाओं का अनुकूलन। - पर्यावरणीय प्रभावः ईंधन के माध्यम से कम उत्सर्जन के माध्यम से सुधार।

5. चुनौतियाँ और सीमाएँ

- पर्यावरणीय परिवर्तनः प्रतिकूल मौसमी स्थितियाँ, कम-प्रकाश परिवेश, ऑक्लूजन। - सजीवता और विश्वसनीयताः विविध परिदृश्यों में लगातार प्रदर्शन की खामियों का सुनिश्चित करना। - डेटा गोपनीयता और सुरक्षाः ऑनबोर्ड कैमरों द्वारा एकत्रित संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा। - नियामकीय अनुपालनः स्वतंत्र वाहनों और डेटा उपयोग के लिए कानूनी ढांचे। - नैतिक विचारः एल्गोरिदमिक अवसाद, जवाबदेही, और उत्तरदायित्व के चिंता को समाधान करना।

6. भविष्य के रुझान और दृष्टिकोण

- सेंसर प्रौद्योगिकी में प्रगतिः उच्च रेजोल्यूशन कैमरे, बेहतर लीडार सिस्टम। - एआई एल्गोरिदमों के आगे बढ़नाः अधिक मजबूत और कुशल गहरी सीखने वाले मॉडल्स।
- अन्य उभरती तकनीकों के साथ एकीकरणः एज कम्प्यूटिंग, 5जी कनेक्टिविटी, वृत्तियों का वृत्ति।- मानकों और विनियमों का अवलोकनः स्वायत्त ड्राइविंग और डेटा गोपनीयता के लिए मानकों की सामंजस्यवाद।- साझा और कनेक्टेड मोबिलिटी की दिशाः स्वचालित यात्रा सेवाओं, स्मार्ट नगर पहल।7. मिसालें और उदाहरण- टेस्ला ऑटोपायलटः टेस्ला के स्वचालित ड्राइविंग के उपयोग के बारे में विश्लेषण।- Waymo की स्वचालित टैक्सियांः Waymo की स्वचालित वाहनों के व्यावसायिक उपयोग का अध्ययन।- Mobileye की उन्नत ड्राइवर-सहायता सिस्टमः Mobileye के विज़न-आधारित सुरक्षा समाधानों की जांच।- वोल्वो का आंतरिक मॉनिटरिंग सिस्टमः वोल्वो के ड्राइवर मॉनिटरिंग के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग।- फोर्ड की विनिर्माण रोबोटिक्सः फोर्ड के विनिर्माण लाइन स्वचालन में कंप्यूटर विजन का उपयोग।8. निष्कर्षण- कंप्यूटर विजन के ऑटोमोबाइल उद्योग पर परिणामों के परिणामस्वरूप, आधुनिक सुरक्षा, दक्षता, और स्वतंत्रता के क्षेत्र में कैसे प्रभावित होता है।- मुख्य लाभ, चुनौतियों, और भविष्य के रुझान का संक्षेप।- समाजिक प्रभाव और नैतिक विचारों पर विचार।- कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी के लिए ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन, अनुसंधान, औरसहयोग के लिए कहना।संक्षेप में, कंप्यूटर विजन प्रौद्योगिकी वाहन उद्योग को सुरक्षा, दक्षता, और स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान देने की बड़ी संभावना रखती है। समझदार एल्गोरिदमों और सेंसर प्रणालियों का उपयोग करके, वाहन परिवेश को अपने आसपास समझ, विश्लेषण, और प्रतिक्रिया दे सकते हैं जिससे अप्रत्याशित निष्क्रियता और निर्देशितता से सुरक्षा और विश्वसनीयता मिलती है। हालांकि, इस दृष्टिकोण को अद्यतित करने के लिए विभिन्न तकनीकी, विनियामक, और नैतिक चुनौतियों का सामना करना होगा, साथ ही नवाचार की सीमाओं को बढ़ाते रहने की आवश्यकता है। उद्योग के हितधारक, नीति निर्माता, और शोधकर्ताओं के संगठन के संयुक्त प्रयासों से, कंप्यूटर विजन निस्संदेह यातायात के भविष्य को आकर्षक, बुद्धिमान, और अधिक सांत्वनाप्रद बना सकता है।

ज़िला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक ने एफ़एसटी टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों का सयुक्त रूप से किया औचक निरीक्षण

शाहपुरा। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित कराने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात एफ.एस.टी. दल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इनके कार्यों का औचक निरीक्षण करने जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत तथा जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कावट मंगलवार को नई अरवाड़ पहुंचे तथा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

लोकसभा चुनाव में प्रतिबंधित सामग्री के परिवहन एवं आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए गठित किए गए एफएसटी चेक पोस्ट में प्रत्येक वाहन की जांच के साथ प्रतिबंधित सामग्री व नगदी के परिवहन पर रोक लगाने का कार्य किया जा रहा है। ज़िला कलेक्टर ने नई अरवाड़ के एफएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार वाहनों की सघन जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लगातार टीम वाहनों की जांच के साथ प्रतिबंधात्मक सामग्री या नगदी पाए जाने पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

रायला में पोलिंग बूथ तथा राजकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ज़िला कलेक्टर ने किया निरीक्षण

इसी दौरान ज़िला कलेक्टर शेखावत ने रायला में चुनावी व्यवस्थाओं का जाएज़ा लेते हुए पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। ज़िला कलेक्टर शेखावत रायला में पोलिंग बूथ के निरीक्षण के पश्चात रायला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुँचे जहां ज़िला कलेक्टर शेखावत ने विद्यार्थीयो तथा शिक्षकों की उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। ज़िला कलेक्टर ने विद्यार्थीयो से मिड डे मील में मिल रहे आहार की गुणवत्ता के बारे में बातचीत की तथा सामान्य ज्ञान के सवाल पूछ कर छात्र - छात्राओ के शिक्षा के स्तर की जाँच की। इस दौरान रायला एसएचओ मौक़े पर उपस्थित रहे।

बीजेडी नही मिले उम्मीदवार; कांग्रेस से नेताओं को लाकर पार्टी दिखा रही ताकत!

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वरः बिजेडी का कांग्रेसीकरण! कोंग्रेस पार्टी छोड़ के बिजेड़ी शमिल लोगो को टिकट थामे हुए है। इसका उद्देश्य चुनावी बोझ आयातित कांग्रेसियों के कंधों पर डालना है, जो उनकी अपनी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। 24 मैदान में ज्यादा तर लोगो कांग्रेस से बिजेड़ी के टिकट पर जीत हासिल की है ।अब तक घोषित 15 लोकसभा उम्मीदवारों में से 3 पूर्व कांग्रेस नेता हैं।केंद्रपाड़ा से अंशुमान मोहंती, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सूर राउत राय के बेटे मन्मथ राउत राय को भुवनेश्वर से और कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व सांसद प्रदीप माझी को इस बार बिजेड़ी ने नबरंगपुर से उम्मीदवार बनाया है।

इस दौरान खारियार् के कांग्रेस विधायक अधिराज पानीग्राही, पूर्व कांग्रेस विधायक चिरंजीवी बिस्वाल, बलांगीर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भोई, पारलाखेमुंडी के पूर्व विधायक के. सूर्या ने राव को गले लगाया।

कांग्रेस विधायक तारा बहिनीपति ने कहा कि बीजेडी की पार्टी पर कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । बीजेपी ने कहा, बीजेडी में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही । इसलिए, बिजेड़ी अपनी तथाकथित ए-टीम कांग्रेस से नेताओं को लेकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में बिजेड़ी ने कहा, मुख्यमंत्री के विकास के सपने से प्रेरित होकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के भी कई नेता बीजेडी में शामिल हुए हैं ।

बिजेड़ी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह, जो कभी विपक्षी दल के नेता थे, को राज्यसभा भेजा। इसी तरह कांग्रेस से मानस मंगराज, विक्रम पांडा, चन्द्रशेखर साहू भी अब बीजू जनता दल के बल पर सांसद और विधायक बन गये हैं। इसके अलावा, यह अफवाह है कि बिजेड़ी गंजाम और केंद्रपाड़ा से दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं को टिकट देने की कोशिश कर रही है।

अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस और एक्साइज विभाग ने की संयुक्त बैठक

परिवहन विशेष न्यूज

अमृतसर (साहिल बेरी) भारत चुनाव आयोग के निर्देश पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर और एक्साइज विभाग के सहायक कमिश्नर श्री सुखविंदर सिंह अवैध शराब की तस्करी को लेकर अमृतसर के पुलिस आयुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें प्रोफेशनल्स को तस्करों पर कड़ी नजर रखने और आपसी मेलजोल बढ़ाकर इन तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया. अवैध शराब के कारोबार में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की रणनीति पर समय-समय पर योजनाएं बनाई जाएंगी और आगामी चुनावों के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। बैठक में श्री आलम विजय सिंह, डीसीपी कानून-और-व्यवस्था, अमृतसर, डॉ. दर्पण अहलूवालिया, एडीसीपी सिटी-1, अमृतसर, श्री प्रभजोत सिंह विर्क, एडीसीपी सिटी-2, श्री नवजोत सिंह एडीसीपी सिटी-3, श्री हरपाल सिंह ए.डीसीपी स्पेशल, अमृतसर और तीन जोन के 06 उपमंडल अधिकारी और बैठक में श्री गोतम गोबिंद वैस, ईओ (आबकारी), श्री मनीष गोयल ईओ (आबकारी), श्री इंदरबीर सिंह ईओ (आबकारी), श्री जतिंदर सिंह ईआई और श्री सुनील कुमार ईआई उपस्थित थे।

ढ़ीकोला चौपाल एवं बडेसरा फेक्ट्री में मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित

शाहपुरा। लोक सभा आम चुनाव में मतदाताओं को जागरूक एवं शत प्रतिशत मतदान करने के उद्देश्य से सहायक रिटनिंग अधिकारी निरमा विश्नोई एवं स्वीप प्रभारी ईश्वर लाल मीणा के निर्देश पर स्वीप कला जत्था शाहपुरा के अशोक कुमार शर्मा, दिनेश जांगीड़, शिव चरण शर्मा, कैलाश कोली, भगवान गोस्वामी एवं भगवती जीनगर आदि ने ढ़ीकोला गांव की चौपाल पर मतदाता जागरूकता गीतों एवं प्रमुख चौराहों पर मतदान करने का संदेश प्रसारित सभी ग्रामीण मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलवाई। पंचायत प्रसार अधिकारी सूर्य प्रकाश शर्मा ने सभी मतदाताओं को निर्भीक एवं बिना किसी दबाव के मतदान करने की निर्वाचन विभाग की इस मुहिम से जुड़ने तथा वोटर हेल्पलाइन एप के बारे में समझाया। साथ ही बडेसरा फेक्ट्री के सभी मजदूरों, फेक्ट्री में कार्यरत कारिगरों एवं स्टाफ कर्मचारियों को आगामी लोकसभा आम चुनाव में लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में शत प्रतिशत मतदान कर इस महायज्ञ में मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प दिलाया तथा सभी को मतदाता शपथ दिलवाई । कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी सुखपाल जाट, प्रबंधक प्रकाश सोमानी, हीरा लाल बावरी, मुकेश कुमार, मांगी लाल, गोपाल कुमावत, सुरेश मीणा, शिव लाल कुम्हार, लादी बावरी, सुशीला, मनभर सहित कई मतदाता थे।

भाजपा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल 4 अप्रैल को नामांकन करेंगे दाखिल

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर स्थानीय आजाद चौक में प्रातः 9.30 बजे आयोजित विशाल आमसभा को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि नामांकन कार्यक्रम, विशाल आमसभा एवं लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा जिला कार्यालय पर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति एवं कोर कमेटी की बैठक लोकसभा प्रभारी एवं ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता एवं लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़ जिला संगठन प्रभारी रतनलाल गाडरी, विधायक गोपाल खंडेलवाल, गोपीचंद मीणा, उदयलाल भडाणा, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी, लोकसभा संयोजक शक्ति सिंह कालियास, पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाडा, वरिष्ठ नेता पेंटर सूरज की विशिष्ट उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक में लोकसभा प्रभारी नागर ने 4 अप्रैल की विशाल नामांकन सभा को आठों विधानसभा क्षेत्रों से ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के साथ ऐतिहासिक सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है अतः सभी पदाधिकारियो को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इस हेतु उन्होंने आवश्यक दिशानिर्देश भी प्रदान किए।

जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने इस अवसर पर 4 अप्रैल की नामांकन सभा, 5 अप्रैल को बूथ लेवल पर टिफिन बैठक व 6 अप्रैल को भाजपा स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद त्रिपाठी एवं जिला महामंत्री वेदप्रकाश खटीक ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रबंधन समिति एवं कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।

श्री आईजी गो शाला पतालियावास में क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज

जोधपुर : बिलाडा के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री जीजी माता पाल मंदिर के पास नगरपालिका क्षेत्र में स्थित पतालियावास में द्वितीय बार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रामावि पतालियावास के खेल मैदान में हो रहा है। मंगलवार को श्री आईजी गोशाला पतालियावास क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का पहला मैच महादेव क्लब मण्डला ओर बॉक्सर क्लब बिलाडा की टीम के बीच हुआ। बॉक्सर क्लब के टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 119 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी मण्डला की टीम ने 12 वें ओवर में लक्ष्य का पीछा करते हुए 100 रन ही बना पाई। आयोजक समिति के सदस्य गोविंद सिंह सीरवी रोबड़ी ने खेलों इंडिया तभी तो स्वस्थ रहेगा युवा थीम के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान श्री जीजी माता पाल मंदिर समिति के अध्यक्ष खियाराम राठौड़, स्थानीय पार्षद यादवसिंह भीवराज, स्थानीय विद्यालय से सुनील सीरवी, भाजपा ज़िला सह सयोजक डॉ रमेश राठौड़, युवा उद्यमी सुआलाल गुर्जर, भामाशाह अनिल वैष्णव, अशोक परिहार, अशोक भाकराणी, तेज सिंह, सुनील राठोड़, हेमंत पुनिया, प्रदीप हटेला, प्रेम सिंह, रमेश राठौड़, रवींद्र सीरवी, किशन सीरवी, गिरधारी गुर्जर, राजू गुर्जर, मुकेश दमदारा, मुन्नाराम आदि मौजूद रहे।

ओएनजीसी ने सीएसआर पहल के तहत सफदरजंग अस्पताल को उपलब्ध करवाए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। भारत की शीर्ष ऊर्जा महारत्न, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी), एक प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के माध्यम से समाज की भलाई के लिए अपना योगदान निरंतर देती आ रही है। ओएनजीसी ने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं प्रदान करके नई दिल्ली के शीर्ष चिकित्सा सुविधा सफदरजंग अस्पताल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओएनजीसी और सफदरजंग अस्पताल ने महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण हासिल करने के लिए साझेदारी की है, जिसमें PHACO इमल्सीफिकेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, अल्ट्रासाउंड मशीन, इलेक्ट्रॉनिक बेड, आरओ प्लांट, वॉटर एटीएम, वेन व्यूअर्स, पोर्टेबल मॉनिटर, व्हीलचेयर और ट्रॉलियां शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण योगदान का लक्ष्य समग्र स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करना और मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा उपचार प्रदान करने की अस्पताल की क्षमता में वृद्धि करना है।

आधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जो पूरे समुदायों में सस्ती, प्रथम श्रेणी की स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ओएनजीसी की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रो. (डॉ.) वंदना तलवार, चिकित्सा अधीक्षक एस.जे.एच. ने योगदान किए गए प्रत्येक उपकरण के महत्व और व्यापक उपयोग के विषय में बताया। उन्होंने आगे कहा कि ट्रॉली बेड मरीजों के साथ-साथ मेडिकल स्टाफ के लिए भी बहुत मददगार होगा, जिससे उनका काम आसान हो जाएगा, और यह सुनिश्चित करने के लिए आरओ प्लांट का महत्व कैसे है कि हर किसी को स्वच्छ पानी मिले, जो एक मौलिक मानव है सही।

PHACO इमल्सीफिकेशन प्रणाली एक उन्नत सर्जिकल उपकरण है जो मोतियाबिंद प्रक्रियाओं को सटीक रूप से निष्पादित करने और मोतियाबिंद के रोगियों को उनकी दृष्टि वापस पाने में मदद करने के लिए आवश्यक है। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन को सटीक निदान, रोगी की देखभाल और सुविज्ञ चिकित्सा निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने के अलावा, ओएनजीसी के योगदान से चिकित्सकों और कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

ओएनजीसी के मानव संसाधन निदेशक मनीष पाटिल ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। परियोजना के बारे में बोलते हुए, ओएनजीसी के मानव संसाधन निदेशक, मनीष पाटिल ने जोर देकर कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सामुदायिक कल्याण का समर्थन करती है और सफदरजंग अस्पताल के साथ यह साझेदारी समाज की भलाई के लिए संसाधनों का उपयोग करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सीएसआर गतिविधि के द्वारा, यह हमारे समाज में चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देता है जिससे स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ हो जाती है। कार्यक्रम में कार्यकारी निदेशक चीफ सीएसआर ए.पी. सिंह, डबाशीष मुखर्जी, ओएनजीसी फाउंडेशन के सीईओ सी.एस. राभा और डॉ. राजीव यादव भी उपस्थित थे।

सफदरजंग अस्पताल, एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाले अनगिनत व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है। ओएनजीसी के उदार समर्थन से संभव हुआ आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं का समावेश, निस्संदेह विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य स्थितियों के निदान और उपचार में अस्पताल की क्षमताओं को बढ़ाएगा।

ओएनजीसी के समावेशी विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के बुनियादी मूल्य इस सीएसआर प्रयास में सन्निहित हैं। स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करके, ओएनजीसी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखने और देश भर में सामुदायिक कल्याण को बढ़ाने वाले समग्र विकास को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023